सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
YouTube
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 75, नई दिल्ली, गुरुवार, 12 जनवरी 2023, पेज 8

NEWS NTV TRANSPORT VISHESH
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 30 जनवरी को हो सकता है मेयर चुनाव
05 शाहरुख खान की मौजूदगी में हुई ह्यूंडई आईकॉनिक 5 लॉन्च
08 मोहन भागवत के साक्षात्कार ने सर्द मौसम में बढ़ाया राजनीतिक तापमान

आज का सुविचार

हर दिन अच्छा हो ये जरुरी नही होता. पर हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरुर होता है.

दिल्ली-एनसीआर के 200 किमी के दायरे में चलेंगी प्रीमियम बसें, डीटीसी बोर्ड ने दी मंजूरी, मिलेगी राहत

डीटीसी बोर्ड की बैठक में प्रीमियम इंटरसिटी बसों के परिचालन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

संजय बाटला

दिल्ली। डीटीसी कर्मचारी ई-वाहनों की खरीद के लिए दिल्ली ईवी नीति-2020 के तहत दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) से सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में डीटीसी के संविदा कर्मचारियों को तीन राष्ट्रीय अवकाश का लाभ देने की भी मंजूरी दी है।
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) जल्द ही दिल्ली-एनसीआर के 200 किलोमीटर के दायरे में स्थित शहरों के लिए प्रीमियम बसें चलाएगा। सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस सहित तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस बसें इलेक्ट्रिक या सीएनजी की होंगी। डीटीसी बोर्ड की बैठक में प्रीमियम इंटरसिटी बसों के परिचालन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हरी झंडी मिलने से इंटरसिटी प्रीमियम बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रीमियम बस सेवा की शुरुआत से दिल्ली-एनसीआर के शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बोर्ड ने डीटीसी कर्मचारियों में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए डिपो में मुफ्त चार्जिंग की सुविधा प्रदान करने की भी स्वीकृति दे दी है।
डीटीसी कर्मचारी ई-वाहनों की खरीद के लिए दिल्ली ईवी नीति-2020 के तहत दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) से सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में डीटीसी के संविदा कर्मचारियों को तीन राष्ट्रीय अवकाश का लाभ देने की भी मंजूरी दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री और डीटीसी बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों और दिल्ली के नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं देने में हमेशा सबसे आगे रही है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को डीटीसी की नई प्रीमियम बसों में बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। मुफ्त ईवी चार्जिंग सुविधाएं और संविदा कर्मचारियों को 03 राष्ट्रीय अवकाश का लाभ हमारा अपने कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी प्रीमियम बसें

डीटीसी काफी समय से लंबे मार्गों पर प्रीमियम बसें शुरू करने की योजना बना रहा था। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही एनसीआर के 200 किलोमीटर के दायरे में स्थित शहरों के लिए प्रीमियम बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। अधिक दूरी पर चलने वाली इंटरसिटी बसें भारत स्टेज (बीएस-6) होंगी। लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से बसें आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी।

निशुल्क होगी चार्जिंग

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए डीटीसी बोर्ड ने इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए मुफ्त चार्जिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इसकी मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली ईवी पॉलिसी में दोपहिया वाहनों को प्राथमिकता दी गई है। पहले ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए दिल्ली सरकार प्रति वाहन 5,000 रुपये प्रति किलोवाट ऑवर की बैटरी क्षमता वाले वाहनों को अधिकतम 30 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। फिलहाल डीटीसी के 38,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया कि 45 फीसदी कर्मचारी ऑफिस आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए दूरी की चिंता और वाहनों की चार्जिंग प्रमुख चुनौतियों में से एक है। निशुल्क चार्जिंग की सुविधा मिलने से ई वाहनों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

कई और प्रस्तावों को मंजूरी

डीटीसी कर्मचारी ई-वाहन खरीदने के लिए डीएफसी द्वारा सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। डीटीसी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) द्वारा सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ कर्मचारी के वेतन से सीधे किश्त का भुगतान कर सकेंगे-अब संविदा कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों के समान राष्ट्रीय अवकाश मिलेगा।

इनसाइड

ऑटो एक्सपो 2023 हुआ शुरू

ग्रेटर नोएडा। भारत के लोकप्रिय मोटर शो 'ऑटो एक्सपो' 2023 की बुधवार से यहां पर शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रिक कनसेप्ट एसयूवी 'ईवीएक्स' को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। यह गाड़ी 2025 तक बाजार में आएगी। दो साल में एक बार होने वाला यह शो वैसे तो 2022 में होने वाला था लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार के शो में महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोडा, फॉक्सवैगन और निसान जैसे प्रमुख वाहन विनिर्माता तथा मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी महंगी गाड़ियों की कंपनियां हिस्सा नहीं ले रही हैं। इस शो में पांच वैश्विक पेशकश होंगी और 75 उत्पादों से पर्दा हटेगा। आम जनता 13 से 18 जनवरी के बीच इस शो को देखने जा सकती है। सुजुकी की कनसेप्ट ईवीएक्स मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसकी डिजाइन और विकास सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, जापान ने किया है। इसमें 60 किलोवॉट की बैटरी है और यह एक बार चार्ज करने पर 550 किलोमीटर तक चल सकती है। यहां एक्सपो में वाहन का अनावरण करते हुए सुजुकी मोटर के प्रतिनिधि निदेशक एवं अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने कहा, ''हमारी योजना इसे 2025 तक बाजार में लाने की है। सुजुकी समूह में हमारे लिए ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए समाधान ढूंढना प्राथमिकता है।''

दिल्ली में ऑटो टैक्सी का प्रयोग करना होगा अब महंगा, नोटिफिकेशन जारी

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में अधिकतर ऑटो टैक्सी चालकों की मांग को दरकिनार कर दिल्ली में ऑटो टैक्सी के किराए में करी बढ़ोतरी।
आम आदमी पार्टी से समर्थित ऑटो एसोसिएशन द्वारा इस बढ़ाए हुए किराए के लिए सरकार और विभाग को धन्यवाद किया गया जबकि अन्य सभी ऑटो टैक्सी संस्थाएं इसके विरोधी रहे और उनकी मांग सीएनजी के दाम कम करने या सीएनजी पर सभी ऑटो टैक्सी चालकों को सब्सिडी की मांग आज भी बरकरार है।
दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग आज तक एप बेस्ड कंपनियों पर तो कंट्रोल कर नही सकी और ऊपर से दिल्ली में एप बेस्ड कंपनियों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से दिल्ली में प्रीमियम सेवा शुरू करने को आतुर हैं।
दिल्ली की जनता को आज तक 24 घंटे सुरक्षित सेवा प्रदान करने वालो की सुध लिए बिना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जगह उजाड़ने में व्याकुल है परिवहन विभाग।
एक तरफ़ दिल्ली सरकार फ्री की बात कहते नही थकती और उस पर चार चांद लगाने में परिवहन विभाग पर सभी वाहन मालिकों/चालकों के विरोध करने पर भी ऑटो टैक्सी के किराए बढ़ाने का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

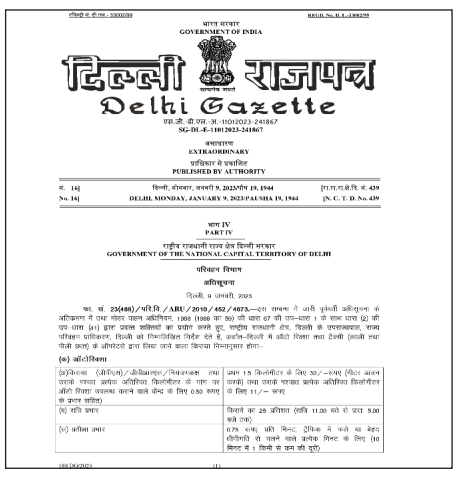

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
GOVERNMENT OF INDIA
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY [PART IV]
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 9th January, 2023
F. No. 23(488)/TPT/ARU/2010/452/4673.—In suppression of earlier notification issued in this behalf and in exercise of power conferred by Sub-Section (1) of Section 67 read with Sub-Section (41) of Section 2 of Motor Vehicles Act 1988 (15 of 1988), The Lieutenant Governor of Nation Capital Territory of Delhi hereby issues the following directions to the State Transport Authority of Delhi namely:-
The fare chargeable by the operators of Auto Rickshaw and Taxi (Black & Yellow Top) in the National Capital Territory of Delhi Shall be as follows:
A). Auto Rickshaw

a	Fare (including Rupees 0.50 charges for global positioning system (GPS)/General packet radio service (GPRS/Control Room)	Rs. 30/- for first fall of 1.5 Km (upon downing the meter) and thereafter Rs. 11 per Km for every additional Kilometer.
b	Night Charges	25% of the fare (11.00 P.M. to 05.00 A.M.)
c	Waiting Charges	Rs. 0.75 paisa per minute for every minute stuck in traffic or moving extremely slow (less than 1 km. covered in 10 minutes).
d	Luggage Charges	Rs. 10 shall be charges per piece, whereas the driver/operator shall not charge any money for shopping bag or a small attaché/suitcase

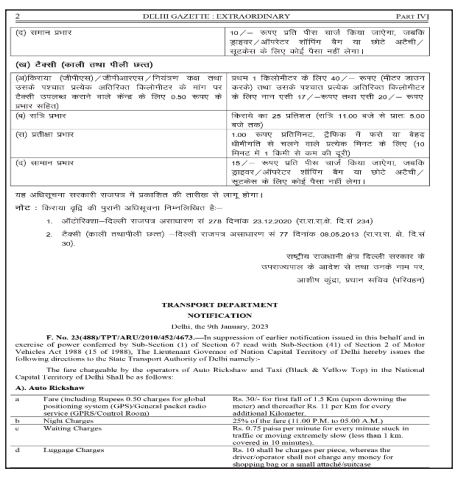

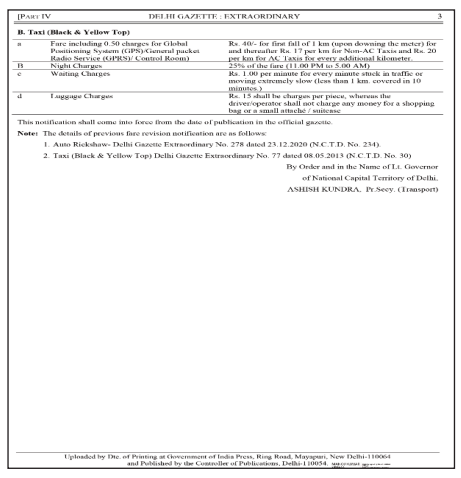

[PART IV] DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
B. Taxi (Black & Yellow Top)

a	Fare including 0.50 charges for Global Positioning System (GPS)/General packet Radio Service (GPRS)/ Control Room)	Rs. 40/- for first fall of 1 km (upon downing the meter) for and thereafter Rs. 17 per km for Non-AC Taxis and Rs. 20 per km for AC Taxis for every additional kilometer.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

हादसों की सड़क

देर रात स्कूटी पर सवार घर लौटती युवती कार में फंसी तकरीबन बारह किलोमीटर तक घिसटती गई और आखिर उसकी मौत हो गई। क्या कार चलाने वाले इतने मासूम हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी से घसीटती लड़की के बारे में सचमुच नहीं पता चला? यह सिर्फ बहाने से ज्यादा कुछ और नहीं लगता! हालांकि कानून अपना काम करेगा ही।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। वर्ष 2020 में कुल 3,66,138 सड़क हादसे हुए, जबकि वर्ष 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,12,432 हो गया।

दिल्ली महिला आयोग ने कंझावला में हुई घटना को महिला के खिलाफ अपराध के वर्ग में डाला है। आयोग ने गृह मंत्रालय से मांग की कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक समिति बनाई जाए। समिति के अंतर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल होने चाहिए।

महिला के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए समिति के महीने में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। सड़क हादसों के आंकड़ों को कम करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी कई पैमाने सुझाए हैं, जिसमें सड़क हादसों को लेकर जागरूकता फैलाने से लेकर वाहनों में एअरबैग लगाने, ब्रेक की व्यवस्था, वाहन चालकों को उचित और जरूरी प्रशिक्षण शामिल है।

इन समाधानों के साथ सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए कई प्रभावशील कानून भी लागू किए हुए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार के प्रयासों से ही सड़क दुर्घटना नहीं रुकेगी। लोगों को भी वाहन चलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए कार में सीट बेल्ट लगाना चाहिए और अगर स्कूटी या बाइक से यात्रा कर रहें हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।

सड़क यातायात के नियमों को पालन करना अपने आप में हादसों से बचाएगा। सड़क पर संवेदनशील होना सबकी जवाबदेही है। लापरवाही या मनमानी न सिर्फ दूसरों की जान ले सकती है, बल्कि इससे खुद अपनी जान भी जा सकती है।

साएमा परवीन, फरीदाबाद, हरियाणा

"सुरक्षित सड़कों के प्रचार के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह"

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी के लिए सुरक्षित सड़कों का प्रचार करने के लिए 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। सप्ताह के दौरान, आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और सभी हितधारकों को सड़क सुरक्षा के लिए योगदान करने का अवसर देने के लिए पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों से संबंधित विभिन्न जागरूकता अभियान शामिल हैं। स्कूल/कॉलेज के छात्रों, ड्राइवरों और अन्य सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ विभिन्न गतिविधियों की भी योजना बनाई गई है।

मंत्रालय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक और संवेदीकरण अभियानों सहित कई गतिविधियों का संचालन करेगा। इसके अलावा, स्कूली छात्रों के लिए निबंध लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे कॉरपोरेट्स/पीएसयू/एनजीओ द्वारा प्रदर्शनी और थिएटर मंडप, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा, दिल्ली में वॉकथॉन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी आयोजित की जाएगी।

इसके अलावा, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल आदि जैसी सड़क की मालिक एजेंसियां पूरे देश में यातायात नियमों और विनियमों के अनुपालन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, चालकों के लिए आंखों की जांच शिविर और सड़क इंजीनियरिंग से संबंधित अन्य पहलों से संबंधित विशेष अभियान चलाएंगी।

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने लगाया प्रदूषण की आड़ में टैक्सी, बस वालों को बेरोजगार करने का आरोप

दिल्ली सरकार के खिलाफ गुरुवार को भारी प्रदर्शन करेंगे ट्रांसपोर्टर्स

एनटीवी ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की दमनकारी नीतियों और प्रदूषण की आड़ मैं टैक्सी बस वालो को बेरोजगार करने की साजिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स 12 जनवरी 2023 को दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ और उनके पर्यवारण मंत्री गोपाल राय और परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत के खिलाफ उनके आम आदमी पार्टी के रास्ट्रीय कार्यालय दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर भारी प्रदर्शन किया जाएगा. कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने स्टेजने ग्रेप 3 लागू किया हैं जबकि मौसम भी दिन में ठीक हें इसके बावजूद दिल्ली मे डीजल की यूरो 4 की सारी प्राइवेट कारो /टैक्सीयों और टेम्पो ट्रेवलर को दिल्ली एनसीआर में बंद करने का फरमान दिल्ली सरकार ने तीसरी बार जारी कर दिया.
दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं की कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेप 3 लागू होने पर ये फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ दिया था.
लेकिन पिछली बार भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी ने प्रदूषण में सुधार होने के बावजूद और AQI की मात्रा कम होने पर यूरो 2 डीजल के हलके मालवाहक ट्रक और बड़े ट्रको की एंट्री भी दिल्ली में खोल लेकिन हमारी यूरो 4 डीजल की टैक्सीयों और टेम्पो ट्रैवेलर को चलाने से बंद कर दिया. इस बार भी 10 जनवरी को तीसरी बार से श्री गोपाल राय पर्यावरण मंत्री जी ने हम गरीब टैक्सी वालो और टेम्पो ट्रैवेलर वालो के साथ दोहरा रवैया अपना कर हमारी यूरो 4 डीजल टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर को बंद करा हैं . जबकि डीजल के यूरो 2 हलके मालवाहक छोटे ट्रक और बड़े ट्रक दिल्ली एनसीआर में सरेआम चल रहें हैं जो की सरासर गलत हे. इन टट्रको की संख्या हजारों में होती हें जो की रात भर दिल्ली में आते हें या दिल्ली के अंदर से ही होकर गुजरते हें. लेकिन दिल्ली सरकार ट्रक वालो से डरती हें इसलिए उन्हें बंद नहीं करती.
ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ये प्रदर्शन इसलिए भी कर रहीं हैं की अभी और भविष्य में दिल्ली सरकार हमारी डीजल की यूरो 4 टैक्सी -टेम्पो ट्रेवलर को बंद ना करें और अगर करें भी तो अभी और भविष्य में हमारी गाड़ियों को रोकने का मुआवाजा दे.ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हे की दिल्ली सरकार ने जिस तरह दिल्ली के टैक्सी वालो और ट्रांसपोर्टर्स की डीजल की गाड़ियाँ बंद करने की साजिश करके टैक्सी वालो को बर्बाद करने की साजिश रची हे उस से साबित होता हैं की इनकी इलेकट्रिक कार बनाने वाली कम्पनियो से मिलीभगत हैं
क्योंकि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही हे जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आम गाड़ियों से 100% से 300 % तक महंगी हे, इनकी रख रखाव भी आम गाड़ियों से 10 गुना महंगा हे और भविष्य में अगर इन गाड़ियों की एक बैटरी भी खराब हो जाए तो एक बैटरी की कीमत भी कम से कम एक लाख रुपय के आसपास होती, और गाड़ियों में काफी बैटरी होती हे, दूसरी बात ये दिल्ली में डीजल की यूरो 6 कारे बिकवाना चाहते हैं और इनको इन कार बनाने वाली कम्पनियो से कुछ फायदा मिल रहा हैं इसकी पूरी सभावना हमें लगती हैं क्योंकि इस बार दिल्ली एनसीआर में डीजल की यूरो 6 गाड़ियों को इन्होने चलने की इज्जाजत दी हैं.
संजय सम्राट का कहना हैं की दिल्ली सरकार के परिवहन बिभाग के इनफ़ोर्समेंट विभाग में सारी इन्नोवा गाड़ियाँ यूरो 4 डीजल की हे, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में जो गाड़ियाँ मंत्रियो की सिक्योरिटी में लगी हे वो भी सारी यूरो 4 डीजल की हे. और तो और दिल्ली पुलिस की सारी पीसीआर वेन यूरो 4 डीजल की हैं.पूरी दिल्ली में हजारों डग्गामारी की यूरो 2 डीजल बसें पूरी दिल्ली से चलती हें. ये सब गाड़ियाँ प्रदूषण फैलाती हें लेकिन दिल्ली सरकार को सिर्फ गरीब टैक्सी वाले और 4 टायर वाली डीजल की गाड़ियाँ नजर आ रहीं हें.
संजय सम्राट का कहना हे की दिल्ली सरकार को सिर्फ प्रदूषण हमारी गाड़ियों में नजर आ रहा हे क्योंकि हमारी गाड़ियों में 4 पहियें हें (4 व्हीलस) जबकि डीजल के ट्रक और डग्गामारी की बसों में 6 पहियें (6 व्हीलस) और वो सब यूरो 2 डीजल गाड़ियाँ हें दिल्ली सरकार का ये दोहरा चरित्र हें और वो जानभूझ कर हमारी गाड़ियों पर भारी भरकम 20 हजार के जुर्माने भी कर रहीं हें.संजय सम्राट का कहना हें की हर साल हम दिल्ली के परिवहन विभाग से प्रदूषण सर्टिफिकेट लेते हे जिस से साबित होता हे की हमारी गाड़ियाँ प्रदूषण नहीं फैलाती, हर 2 सालो में हमारी डीजल गाड़ियों की फिटनेस होती हे जिसमे प्रदूषण सर्टिफिकेट के हर साल हम 120 रुपए और कुछ गाड़ियों के हर 3 महीने में 120 रुपए देते हे. इसमें भी अरबो रूपया का घोटाला हो सकता हैं. क्योंकि इस सर्टिफिकेट की कोई मान्यता दिल्ली सरकार अब नहीं मान रहीं और इसलिए हमारी डीजल की यूरो 4 गाड़ियों को प्रदूषित बता कर बंद कर रहीं हें.ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने काफी गाड़ियों की बुकिंग केन्सिल की हैं जिस से पर्यटको में असंतोष हैं और हमें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा हैं.

संजय सम्राट, अध्यक्ष
दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन.
98101821479717906644011-40518321

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

प्रेग नेंसी में मोबाइल रेडिएशन से दूरी बनाना जरूरी वरना शिशु को हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम

अगर गर्भवती महिला के आसपास अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन है, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है. यही नहीं, बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है. जानें, प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल रेडिएशन से अजन्मे बच्चे के विकास में क्या समस्या आ सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है. हम सभी सुनते आए हैं कि अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है. खासतौर पर प्रेग्नेंट महिला और उसके पेट मे पल रहे बच्चे के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पेट में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी तक हो सकती है. केवल मां ही नहीं, अगर मां के आस पास लोग वायरलेस चीजों का अधिक इस्तेमाल कर रहे है तो इसका भी भ्रूण में पल रहे बच्चे पर खराब असर पड़ सकता है. मॉमजंक्शनमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में किए गए शोध में पाया गया है कि अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन में अगर गर्भवती मां रहती है तो जन्म के बाद बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. यही नहीं, इसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं.

वायरलेस डिवाइस कैसे करता है प्रभावित

दरअसल जब हम मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह के वाइफाई या वायरलेस डिवाइस के संपर्क में आते हैं तो इससे हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स निकलते रहते हैं. ये वेव्स हमारे शरीर के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं और हमारे शरीर में बन रहे जीवित सेल्स के मोलक्यूल्स को बदल सकते हैं. जिसका असर लॉग टर्म काफी खतरनाक हो सकता है. चूंकि भ्रूण हर वक्त ग्रोथ कर रहा है ऐसे में उसके डीएनए और लीविंग सेल्स आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं. जिसका दूरगामी असर भी काफी खतरनाक हो सकता है.

क्या कहता है शोध

अलग अलग शोधों में पाया गया कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन अगर मां और बच्चा 24 घंटे मोबाइल रेडिएशन के बीच हैं तो बच्चे की मेमोरी, ब्रेन ग्रोथ और बिहेवियर में खतरनाक रूप से समस्या आ सकती है. शोधों में यह भी पाया किया गया कि प्री और पोस्ट डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. यही नहीं, बच्चे की भाषा, संचार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

इस तरह करें बचाव

- घर में जहां तक हो सके वाई फाई या ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल कम करें.
- बेहतर होगा अगर आप मोबाइल की बजाय लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल करें.
- रेडियो, माइक्रोवेव, एक्सरे मशीन आदि से दूरी बनाएं.
- मोबाइल टावर आदि के आस पास घर ना लें.

गर्भावस्था में मोबाइल के नुकसान

-गर्भवती महिलाओं में रेडिएशन से मस्तिष्क की गतिविधि पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे थकान, चिंता और नींद में रुकावट पैदा होती है.
-गर्भावस्था के दौरान रेडियो वेव्स के लगातार संपर्क से आगे जाकर कैंसर का खतरा बन सकता है.
-मां गर्भावस्था के दौरान फोन का अधिक इस्तेमाल करे या काफी करीबी लोग घर पर इसका इस्तेमाल करें तो बच्चे के व्यवहार में 50 प्रतिशत बदलाव देखने को मिलता है.

आप भी पुरानी बातों को लेकर रहती हैं बेचैन? इन 4 तरीकों से जिंदगी बनाएं खुशहाल, मिलेगी हर मंजिल

अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर बने, तो अपने पुराने निर्णयों को स्वीकारना शुरू करें और उन्हें जीवन में बड़ी सीख की तरह देखें. ऐसा करने से आप उन्हें जीवनभर बोझ बनाकर ढोने से बच जाएंगी और आगे बेहतर तरीके से जी सकेंगी.

अगर आपको इस बात का पछतावा रहता है कि आपके कुछ गलत निर्णयों की वजह से आपकी जिंदगी आज बुरे हालातों से गुजर रही है तो ऐसा सोचने वाली अकेली आप नहीं हैं. खासतौर पर अगर आपने अपने किसी निर्णय की वजह से कुछ बहुत ही खास चीज को खो दिया है या जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है तो ये पछतावा आपको जीवनभर के लिए अवसाद में जीने को मजबूर कर सकता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप पुराने पछतावों से किस तरह खुद को उबार सकती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं.

पुराने पछतावों से खुद को ऐसे उबारें

लिस्ट बनाएं

जीक्यूइंडियाके मुताबिक, पछतावों से खुद को उबारने के लिए उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपने अपनी गलतियों से सीखी है. दरअसल गलत निर्णय जीवन में सीख की तरह होते हैं. अगर आप इन्हें सकारात्मक तरीके से स्वीकारें तो ये आपको जीवन में आगे होने वाली गलतियों से आपको बचा सकते हैं. इस तरह आप खुद की गलतियों को यादा करें और उनसे सीख लें. इस तरह आप बेहतर डिसीजन मेकर बन पाएंगी.

खुद को करें माफ

गलतियों की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने और खुद का सजा देने की बजाय बेहतर होगा कि आप खुद को माफ करें. ऐसा करने से आप चीजों को भूलकर आगे खुशहाल रहेंगी और आगे जजमेंटल होकर निर्णय नहीं लेंगी.

अपने पछतावों को लिखें

आप अपने अंदर पल रही निगेटिव फीलिंग्स को दूर करने के लिए अपने पछतावों को एक जगह लिखें और विचार करें कि क्या ऐसा ना होने पर आपकी जिंदगी सच में बदली होती ! यकीन मानिए, आपके सवालों का जवाब आपको जैसे ही मिल जाएगा आप पछतावों से छुटकारा पा जाएंगी.

इस विषय पर करें बात

अगर आपको यह लग रहा है कि आप अपने पछतावों के तले दबा हुआ और घुटन सा महसूस कर रही हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी अपने विश्वसनीय से इस विषय पर बात करें. कई बार अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेने और खुलकर बात कर लेने से भी बेहतर महसूस होता है.

बिज़ी लाइफ में इन तरीकों से महिलाएं निकालें खुद के लिए समय

महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टस्क हो गया है. महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टस्क हो गया है.

कामकाजी महिलाओं (Working Women) के ऊपर घर के साथ-साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है. ऐसे में कुछ तरीकों की मदद से वे अपना काम आसान कर सकती हैं और अपने लिए समय बचा सकती हैं ताकि वे अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकें.

आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टास्क हो गया है. इस समस्या से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हैं और जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए तो खुद के लिए समय निकालना नामुमकिन है. वर्किंग विमेन (Working Women) के ऊपर घर के साथ-साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है. जिसे पूरा करते-करते वे ना तो चैन की सांस ले पाती हैं और ना ही अपनी नींद पूरी कर पाती हैं. ऐसे में स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर पड़ता है.

इस समस्या को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम कुछ ऐसे हैक्स बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं.

चाबियों पर लगाएं अलग-अलग रंग की नेल पॉलिश

अक्सर जब किसी काम को जल्दी पूरा करना हो या हम जब जल्दी में होते हैं तभी छोटी-छोटी चीजों की वजह से देर होने लगती. ऐसे में आप अपने घर की कई चाबियों को अलग-अलग रंग की नेल पॉलिश से रंग सकते हैं. इससे आपको पर्टिकुलर लॉक के लिए सारी चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं.

कंघी करते समय रखें ध्यान

ऑफिस जाते समय जल्दी-जल्दी में बालों को सुलझाने में महिलाएं बालों के साथ खींचतान करने लगते हैं. जिससे बाल अधिक टूटते हैं और नीचे गिर कर काम बढ़ा देते हैं. इससे बचने के लिए अपने हेयर ब्रश में बटर पेपर लगाकर कंघी करें. इससे बाल जल्दी सुलझ जाएंगे और नीचे भी नहीं गिरेंगे.

हेयर स्ट्रेटनर से प्रेस करें

सुबह के समय जल्दी रहे तो आप प्रेस के लिए हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपके कपड़े जल्दी प्नेस होंगे और आपका समय बच जाएगा.

कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ये ऐप्स

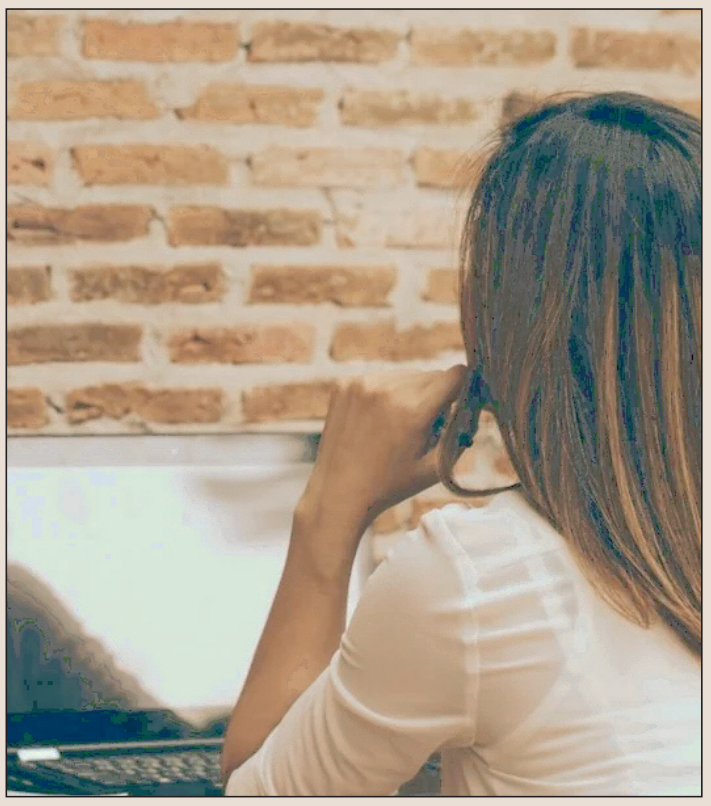

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है.

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और अन्य मेट्रो सिटीज में ऐप्स की मदद से आगे बढ़ रही हैं और पैसे भी कमा पा रही हैं. सबसे खास बात यह है कुछ प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका नहीं अपनाना पड़ता, जिससे उनकी झिझक कम हो जाती है.

अगर आप किसी कारणवश अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई हैं, या आपने केवल 10वीं या 12वीं तक की ही पढ़ाई की है और आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, इस अब आपको ऐसा मौका मिल सकता है. क्योंकि देश में कई ऐसे मोबाइल ऐप बनाए गए हैं, जो खासरकर महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. इन ऐप्स के इस्तेमाल से महिलाओं ने 2021 में तरक्की के कई रास्ते खोले और अब 2022 में भी ये उनकी मदद कर रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर (**Delhi-NCR**), मुंबई, हैदराबाद, पुणे और अन्य मेट्रो सिटीज में बहुचर्चित 'अपना (**apna**)' ऐप ने महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ बनाई है. बीते साल करीब लाखों महिलाओं ने इसका इस्तेमाल कर नौकरी पाई. सबसे खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका नहीं अपनाना पड़ता, जिससे उनकी झिझक कम हो जाती है.

इन ऐप्स पर सिर्फ अपनी जानकारी डालने के बाद उनके पास जरूरत के हिसाब से नौकरी पाने के ऑफर आते रहते हैं. 12वीं पास महिलाओं ने सबसे ज्यादा टेलीकॉलर, बीपीओ, बैक ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस, टीचर, अकाउंटेंट, एडमिन ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए आवेदन किया है.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत प्लेटफॉर्म

इसी तरह खास महिलाओं के लिए चलाई जा रही सोशल नेटवर्किंग साइट 'शीरोज (**Sheroes**)' भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई है. यहां हर उम्र वर्ग की महिलाएं, ऐप या वेबसाइट के माध्यम से जुड़ती हैं. वह नौकरी के अवसर भी तलाशती है, साथ ही अगर वह अपने लेवल पर किसी तरह का बिजनेस कर रही हैं, तो उसे प्रमोट भी करती हैं. बिजनेस वुमेन इसके सहारे अपना नेटवर्क मजबूत कर रही हैं. इस तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई.

जो महिलाएं मां नहीं बन पातीं, उनमें हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा: नई रिसर्च

महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है.

महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है. (सांकेतिक तस्वीर) महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है.

ब्रिटेन में हुई रिसर्च से पता चला है कि जिन औरतों में बांझपन (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका 16 फीसदी तक ज्यादा होती है. महिला को गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ में परेशानी हो तो बाद के सालों में दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है.

प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी

प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी

लंदनः एक नए शोध से पता चला है कि महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने (infertility) की समस्या का संबंध दिल की बीमारी से भी होता है. ब्रिटेन में हुई रिसर्च के बाद दावा किया गया है कि जिन औरतों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका बाकी महिलाओं से 16 फीसदी तक ज्यादा होती है.

अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जर्नल में छपे इस शोध में कहा गया है कि महिलाओं के प्रजनन इतिहास से काफी हद तक पता चल जाता है कि उन्हें भविष्य में दिल की बीमारी होने का कितना खतरा है. महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है.

इस शोध के दौरान दो तरह के हृदयाघात यानी हार्ट फेल होने की स्टडी की गई. पहला preserved ejection fraction के साथ हार्ट अटैक (HFpEF) जिसमें दिल की मांसपेशियां खून पंप करने के बाद पूरी तरह फैल नहीं पातीं. दूसरा हार्ट फेल्योर विद reduced ejection fraction (HFrEF). इसमें बाएं वेंट्रीकल यानी दिल के निचले भाग के कोष से हर धड़कन के बाद जितना खून शरीर में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता. महिलाओं में हार्ट फेल के ज्यादातर मामले HFpEF के ही होते हैं.

शोध करने वाली टीम की लीडर और मैसाचूसेट्स जनरल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एमिली लाउ ने बताया कि रिसर्च के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि महिलाओं में थायरायड या जल्दी मेनॉपॉज़ जैसी समस्याओं का भी क्या प्रजनन क्षमता और दिल की बीमारी से कोई लेना-देना होता है या नहीं. लेकिन इस धारणा को लेकर किसी तरह के पुख्ता सबूत अभी नहीं मिल पाए हैं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी तक ये तो पता था कि जिन महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की समस्या होती है, उनमें हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांस ज्यादा होते हैं. लेकिन बांझपन का दिल की बीमारी पर असर को लेकर कोई पुख्ता स्टडी नहीं हुई थी. आमतौर पर दिल की बीमारी को 50 साल के बाद की समस्या माना जाता है, जबकि बांझपन उम्र के 20वें, 30वें या 40वें पड़ाव पर आने वाली दिक्कत है. इसलिए इन दोनों के संबंध पर गौर नहीं किया जाता. अब महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की क्षमता का कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन भविष्य का ध्यान तो रखा ही जा सकता है ताकि उन्हें दिल की बीमारियों से बचाया जा सके.

इनसाइड

आईएएस अधिकारी के महेश का ट्रांसफर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की कार्रवाई

दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईएएस अधिकारी के महेश को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के सीईओ के रूप में स्थानांतरित कर दिया है। बता दें कि एलजी ने 23 दिसंबर को अपने निरीक्षण के दौरान रैन बसेरों में शौचालय सुविधाओं की कमी और लोगों की भीड़भाड़ पाई जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आईएएस अधिकारी के महेश अब यूटीसीएस के विशेष निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तैनात नहीं होंगे शिक्षक, DDMA ने वापस लिया फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली हवाईअड्डे पर स्कूली शिक्षकों को कोविड ड्यूटी पर तैनात करने के अपने आदेश को डीडीएमए ने वापस ले लिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक दिल्ली हवाईअड्डे पर स्कूली शिक्षकों को कोविड ड्यूटी पर तैनात करने के अपने आदेश को वापस लिया। प्राधिकरण का कहना है कि जरूरत पड़ने पर हवाई अड्डे पर सिविल डिफेंस स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

चांदनी महल इलाके में मकान की छत गिरी, छह लोग दबे, मां-बेटे की मौत

नई दिल्ली। पुलिस ने बताया कि चांदनी महल इलाके में चितली कबर स्थित एक मकान की छत गिरने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि वहां मलवा फैला पड़ा है। मां-बेटे की मौत हो चुकी है। चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक मकान की छत गिरने से छह लोग उसमें दब गए, जिनमें से मां-बेटा समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि चांदनी महल इलाके में चितली कबर स्थित एक मकान की छत गिरने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि वहां मलवा फैला पड़ा है। मां-बेटे की मौत हो चुकी है। चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मलवे में दबकर रुकसार (30) व उसके बेटे आलिया (3) की मौत हो गई। एक बच्चे की हालत गंभीर है। रुखसार बच्चों को लेकर मायके आई हुई थी। तड़के लगभग 4.45 बजे हादसे के समय वह कमरे में सो रही थी।

कड़ाके की ठंड के बीच 5500 मेगावाट हो सकती है बिजली की पीक डिमांड, पिछले साल था ये हाल

नई दिल्ली। ठंड में कंपनियों ने अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की है, ताकि आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। टाटा पावर बिजली कंपनी को उम्मीद है कि इस सीजन में पीक डिमांड 1650 मेगावाट के आंकड़ा को पार कर जाएगी और इसे पूरा करने के लिए लंबी अवधि के पावर टाई-अप किया गया है। कड़ाके की ठंड में बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इस बार दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 5500 मेगावाट तक पहुंच सकती है। पिछले साल की सर्दियों में यह मांग 5104 मेगावाट तक पहुंची थी। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन (टाटा पावर-डीडीएल) ने 1521 मेगावाट की रिकॉर्ड मांग दर्ज की है। सोमवार को 4803 मेगावाट पीक डिमांड पहुंच गया।

30 जनवरी को हो सकता है मेयर चुनाव, निगम ने उपराज्यपाल को भेजी रिपोर्ट

छह जनवरी को हुई कार्यवाही का विवरण निगमायुक्त की ओर से दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है

एनटीवी संवाददाता

निगम ने मेयर चुनाव को लेकर उपराज्यपाल को रिपोर्ट भेज दी है। माना जा रहा है कि अब 30 जनवरी को मेयर चुनाव हो सकता है। निगम ने उपराज्यपाल से 30 जनवरी को बैठक कराने की अनुमति मांगी है।

नई दिल्ली। नव निर्वाचित पार्षदों की शपथ कराने और महापौर और उप महापौर का चुनाव कराने की नई तारीख कब होगी, इस पर उपराज्यपाल (एलजी) निर्णय लेंगे। हालांकि निगम ने इसके लिए 30 जनवरी की तारीख का प्रस्ताव राजनिवास को दिया है। छह जनवरी को हुई कार्यवाही का विवरण निगमायुक्त की ओर से दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व में निर्धारित तारीख के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने शपथ तो ले ली, लेकिन हंगामे के चलते अन्य पार्षदों की शपथ नहीं हो पाई। ऐसे में एलजी से निगम ने अगली बैठक की तारीख निर्धारित करने का आग्रह किया है।

एलजी करेंगे अगली तारीख तय

दिल्ली नगर निगम से जुड़े सूत्रों के अनुसार जो फाइल भेजी गई है उसमें सदन की कार्यवाही का पूरा विवरण दे दिया गया है। अब एलजी ही अगली तारीख तय करेंगे। चूंकि पूर्व में नियुक्त पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा की शपथ हो चुकी है। ऐसे में यह निर्णय एलजी को लेना है कि वे सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त फिर से करें या फिर किसी और सदस्य को पीठासीन अधिकारी बनाएं।

दिल्ली नगर निगम के एक्ट के अनुसार पार्षदों के निर्वाचन के बाद जो पहली बैठक होती है उसमें एलजी की ओर से नियुक्त एक अधिकारी पीठासीन अधिकारी को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद सभी सदस्यों को पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाते हैं।
इसके बाद महापौर-उप महापौर और स्थायी समिति के लिए छह सदस्यों का निर्वाचन होता है। छह जनवरी को एलजी की ओर से नियुक्त पीठासीन अधिकारी की शपथ तो हो गई थी, लेकिन जैसे ही सत्या शर्मा ने मनोनीत सदस्यों की शपथ करानी शुरू की तो हंगामा हो गया था।

16 सप्ताह का गर्भ गिराने के लिए नाबालिग लड़की ने दाखिल की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को एक नाबालिग लड़की की याचिका पर सुनवाई करेगा। लड़की ने 16 सप्ताह के गर्भ को गिराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उसने अपनी मां के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट 14 साल की एक नाबालिग लड़की की याचिका पर सुनवाई करेगा। नाबालिग लड़की की यह याचिका 16 सप्ताह के गर्भ गिराने से जुड़ा है। 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपनी मां के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने याचिका में 16 सप्ताह के गर्भ का चिकित्सीय समापन चाहती है।

बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं लड़की

बता दें कि लड़की ने याचिका में बताया कि वह बच्चे को पालने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। नाबालिग एक अविवाहित लड़की है और उसके पास एक नाबालिग लड़के के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद गर्भ धारण कर लिया। अदालत बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

पुलिस में बिना रिपोर्ट के दाखिल की याचिका

लड़की की मां ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में गर्भपात कराने की मांग करने वाले अधिवक्ता अमित मिश्रा की मदद से याचिका दायर की है। खास बात है कि परिवार ने सामाजिक कलंक, बहिष्कार और उत्पीड़न के डर से पुलिस में बिना रिपोर्ट किए ही यह याचिका दाखिल की है। हालांकि, POCSO अधिनियम के तहत स्थानीय पुलिस को इस मामले की सूचना देना अनिवार्य है।

गर्भपात कराने पर है यह शर्त

बता दें कि यदि पंजीकृत चिकित्सक का मानता है कि महिला का जीवन गर्भ धारण करने से गंभीर खतरे में होगा तो, चिकित्सा गर्भापात गर्भावस्था अधिनियम 20 सप्ताह तक के गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। याचिका में यह भी कहा गया कि 6 जनवरी, 2023 की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार, इस लड़की में गर्भावस्था 15 सप्ताह और चार दिनों की है।

पार्षदों के बीच हाथापाई को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, निगम के गठन में देरी के लिए AAP को बताया जिम्मेदार

एनटीवी संवाददाता

भाजपा का आरोप है कि आप विधायकों व पार्षदों के हंगामे के कारण निगम के गठन में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उपराज्यपाल को पत्र लिखकर संविधान के उल्लंघन के झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्हें सहयोग करना चाहिए।

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) हाउस की बैठक में हुए हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने निगम के गठन में देरी के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। ताजा मामले में आज बुधवार सुबह दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा ने एमसीडी हाउस की बैठक में हुए हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आईटीओ चौराहे पर प्रदर्शन किया है।

निगम के गठन में देरी को आप जिम्मेदार: बिधूड़ी

भाजपा ने आरोप लगाया है कि आप के कारण नगर निगम के गठन में देरी हो रही है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी के अन्य नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ

बेबुनियाद आरोप लगाने व लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। आप विधायकों व पार्षदों के हंगामे के कारण निगम के गठन में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उपराज्यपाल को पत्र लिखकर संविधान के उल्लंघन के झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्हें सहयोग करना चाहिए।

यमुना सफाई में विफल रही है केजरीवाल सरकार: भाजपा

यमुना पदी की सफाई को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा उपराज्यपाल की अध्यक्षता में समिति गठित करने पर भाजपा ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। उसका कहना है कि यमुना नदी की सफाई में दिल्ली सरकार के विफल रहने के कारण एनजीटी ने यह कदम उठाया है।

प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रत्येक मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने एलजी को पत्र लिखकर प्रत्येक निगम वार्ड में दो पूजा सामग्री केंद्र बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूजन सामग्री विसर्जन से भी यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है।

चोरी के शक में कार सवारों ने की युवक की पीटकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में कार सवार हमलावरों ने चोरी के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के दौरान मृतक के तीन दोस्त मौके से फरार हो गए। शुरुआती जांच में मृत युवक अपने दोस्तों के साथ चोरी की नीयत से सन्नौथ गांव गया था। एक दुकान के पास दो कारों को अपनी ओर आता देख सभी भागने लगे।

इनमें से एक को कार सवार लोगों ने पकड़कर हॉकी से पिटाई कर दी। अगले दिन पुलिस को मृतक का शव बरामद हुआ। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। मृतक की शिनाख्त बवाना निवासी अमजद अली के रूप में हुई है। बवाना निवासी अली हसन ने बताया कि 17 दिसंबर की देर रात वह अमजद अली, इरफान और गुलफान के साथ सन्नौथ गांव चोरी की नीयत से गया था। सभी एक दुकान के पास खड़े थे। इसी दौरान उनलोगों ने दो कारों को अपनी ओर आते देखा। वह देखकर सभी वहां से भागने लगे।

कार सवार लोगों ने उनका पीछा किया। उन लोगों ने अमजद अली को पकड़ लिया और उसकी हॉकी से जमकर पिटाई की। वे कह रहे थे कि आज चोर की हत्या कर देंगे। बाकी सब उसे छोड़कर अपने घर आ गए। यहां आकर उन लोगों ने किसी को वारदात के बारे में नहीं बताया।

अमजद के घर नहीं पहुंचने पर अगले दिन उसकी मां अली हसन के घर पहुंची और उसके बारे में पूछताछ करने लगी। अली हसन ने अमजद के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। शक होने पर उसकी मां ने पुलिस को मौके पर बुला लिया।

पेट्रोलिंग जितनी अधिक होगी, अपराध उतने ही कम होगा - पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह

एनटीवी संवाददाता

दस साल पहले और वर्तमान के दिल्ली-एनसीआर में काफी अंतर है। इस दौरान जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन उस हिसाब से कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए संसाधन नहीं बढ़ाए गए। स्थिति में सुधार करना है तो सबसे पहले पुलिस महकमे में रिक्त भर्तियों की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

नई दिल्ली : दस साल पहले और वर्तमान के दिल्ली-एनसीआर में काफी अंतर है। इस दौरान जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए संसाधन नहीं बढ़ाए गए। दिल्ली-एनसीआर में अगर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना है तो सबसे पहले पुलिस महकमे में रिक्त भर्तियों की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। महिला पुलिसकर्मियों की अधिक तैनाती करनी होगी।

पेट्रोलिंग जितनी अधिक - अपराध उतना कम

जनशक्ति के साथ ही वाहनों की कमी को भी दूर करना होगा, तभी हर घटना के बाद अल्प समय में पुलिस त्वरित सहायता प्रदान कर सकेगी। इसके अलावा सर्विलांस का दायरा और अधिक मजबूत करना होगा। हाल ही में दिल्ली में एक घटना हुई, जिसमें शामिल एक महिला का मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन उस पर पुलिस की नजर प्रारंभिक चरण में नहीं गई। धीरे-धीरे चीजें पता चलीं। अगर अपराधियों पर निगरानी नहीं होगी तो अपराध पर अंकुश लगा पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है।

अभिलेखों और साक्ष्य संकलन में लचीलापन भी कानून और व्यवस्था को खोखला बना देता है। किसी भी अपराधी की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। पेट्रोलिंग जितनी अधिक होगी अपराध उतना ही कम होगा। सिक्योरिटी प्रोसिडिंग पर भी जोर देना होगा।

सामुदायिक पुलिसिंग

दिल्ली का दायरा बदल गया, लेकिन पुलिसिंग वही है। एक पुलिसकर्मी हजारों लोगों की गतिविधि पर नजर नहीं रख पाता। हाइराइज बिल्डिंगों तक पुलिस की पहुंच कम है। ऐसे में आरडब्ल्यूए ओर एओए पदाधिकारियों सहित अन्य सेक्टरों और सोसायटियों के लोगों से संपर्क करना होगा, उनके सुझाव लेने होंगे। नागरिक सुरक्षा संगठन इकाई बनाकर उसपर काम करना होगा। इंटरनेट मीडिया के विविध प्लेटफार्म पर सोसायटी

और सेक्टरों के लोगों को जोड़ना होगा ताकि वह अपनी परेशानी आसानी से पुलिस से साझा कर सकें।

स्ट्रांग कंट्रोल रूम

पहली ही काल पर कंट्रोल रूम को अलर्ट होना होगा। समय की मांग के अनुसार कंट्रोल रूम को और स्ट्रांग बनाना होगा और आधुनिक तकनीकों से लैस करना होगा। त्वरित सहायता मिलेगी तभी लोगों की धारणा पुलिस और पुलिसिंग के प्रति बढ़ेगी। कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की संख्या में इजाफा करना होगा।

स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाना आवश्यक

स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाने की आवश्यकता है। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखनी होगी और इन स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग और गश्त को बढ़ाना होगा। अधिक से अधिक सूत्र तैयार करने होंगे ताकि वह अपराध होने से पहले ही जानकारी मुहैया करा सकें। छात्राओं और महिला कामगारों के लौटने का जो संवेदनशील समय है, उस पर पुलिस का पूरा फोकस होना चाहिए।

1930 पर कॉल कर करें साइबर ठगी की शिकायत

गाजियाबाद। साइबर फ्राड होते ही 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ठगी होने के बाद जितना जल्दी संभव हो शिकायत करें। ऐसे में आपसे ठगी गई रकम वापस मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस नंबर पर शिकायत अधिकांश 72 घंटे तक दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराने के दौरान आप अपने पास यूटीआर नंबर (यूनिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड) या ट्रांजेक्शन आईडी या यूपीआई रेफ्रेंशन नंबर साथ रखें जो शिकायत दर्ज कराने के दौरान पूछी जाएंगी। ये बातें अमर उजाला कार्यालय में सोमवार शाम हुई ठगी से बचने के लिए क्या करें कार्यशाला के दौरान एसीपी अपराध भास्कर वर्मा और उनकी साइबर एक्सपर्ट टीम के एसआई रतन सिंह और हेड कांस्टेबल नागेंद्र सिंह ने बताई।

एसीपी अपराध भास्कर वर्मा ने बताया कि जैसे किसी को अनजान व्यक्ति से बात करने से बचना चाहिए वैसे ही साइबर अपराध में किसी भी अनजान लिंक, नंबर या कॉलर से बचकर साइबर ठगी से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ठगी से बचने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना होगा। अगर किसी को ऑनलाइन खरीदारी या किसी भी ऑनलाइन कार्य को करने की पूरी जानकारी है तो ही करें अन्यथा बिना पूरी जानकारी के ऑनलाइन खरीदारी करने से बचें।

लिफ्ट में कुत्ता ले जाने पर विवाद, पुलिस ने की कार्रवाई

डीसीपी सेंट्रल राम बदन सिंह का कहना है कि विवाद में मुकुंद ने एक व्यक्ति पर पेपर स्प्रे से हमला किया था। साथ ही वह काफी उग्र भी हो गए थे। सोसायटी के लोगों ने घटना की शिकायत की थी।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में स्थित जेएम फ्लोरेंस सोसायटी में लिफ्ट में कुत्ते के मुंह में बिना मजल लगाए ले जाने पर विवाद हो गया। विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक पक्ष खिलाफ शांतिभंग की धारा में कार्रवाई की है। सोसायटी में इंजीनियर मुकुंद कुमार रहते हैं। उन्होंने एक पामेलियन कुत्ता पाला हुआ है। 23 दिसंबर को वह लिफ्ट में कुत्ता लेकर जा रहे थे। उनका आरोप है कि सोसायटी के एक व्यक्ति ने कुत्ते को बिना मजल ले जाने का विरोध किया और उनके साथ मारपीट की। मुकुंद के पास पेपर स्प्रे था, उन्होंने हमला करने वाले पर स्प्रे डाल दिया। मुकुंद का कहना है कि उन्हें बचाने के लिए पत्नी व बच्चे आए, आरोप है कि आरोपित ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उनका कहना है कि पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की है। डीसीपी सेंट्रल राम बदन सिंह का कहना है कि विवाद में मुकुंद ने एक व्यक्ति पर पेपर स्प्रे से हमला किया था। साथ ही वह काफी उग्र भी हो गए थे। सोसायटी के लोगों ने घटना की शिकायत की थी। शिकायत पर मुकुंद के खिलाफ शांतिभंग करने की कार्रवाई की गई है।

गाजियाबाद में लिवर फटने से ऑटो चालक की हुई थी मौत, चौकी प्रभारी निलंबित

एनटीवी न्यूज

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धर्मपाल के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। डा. अनिल विश्वकर्मा डा. नीरज और डा. डीके वर्मा के पैनल ने रविवार रात में धर्मपाल यादव के शव का पोस्टमार्टम किया। उसकी वीडियोग्राफी कराई गई।

गाजियाबाद। ऑटो चालक धर्मपाल की मौत लिवर, गुर्दा व तिल्ली फटने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसकी जानकारी हुई है, हालांकि विसरा सुरक्षित रखा गया है। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन डा. दीक्षा शर्मा ने मामले में नामजद कनावनी पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अमित कुमार को मंगलवार को निलंबित कर दिया।

दो सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के लिए पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट भेज दी। डा. अनिल विश्वकर्मा, डा. नीरज और डा. डीके वर्मा के पैनल ने रविवार रात में धर्मपाल यादव के शव का पोस्टमार्टम किया। उसकी वीडियोग्राफी कराई गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धर्मपाल के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। सिर्फ पैर के दोनों घुटनों पर खरोंच थी। लिवर, गुर्दा और तिल्ली फटी थी। इन्हीं तीनों अंगों के फटने से उनकी मौत हुई थी। प्रकरण काफी चर्चित होने के कारण पुलिस ने विसरा भी सुरक्षित रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सके।

चोट लगने का कारण पता करना कठिन

पुलिस का कहना है कि किसी भारी वस्तु से दबने से ऐसा होता है कि शरीर के बाहरी हिस्सों में चोट के निशान नहीं होते हैं। एक घंटे चला पोस्टमार्टम सोमवार रात में 12 से एक बजे तक धर्मपाल यादव के शव का पोस्टमार्टम हुआ। रात में ही पुलिस ने उसके शव को गृह जनपद कासगंज भेजवा दिया।

बता दें कि ग्राम नागला थाना बांसगांव जिला कासगंज के 28 वर्षीय धर्मपाल यादव यहां कनावनी में किराए पर रहते थे। वह ऑटो चलाकर अपना जीवनयापन करते थे। रविवार रात कनावनी पुश्ता पर उनकी ऑटो से साइकिल सवार की टक्कर हुई थी। पुलिस उन्हें कनावनी पुलिस चौकी लाई थी। रात में एक बजे छोड़ा था। सोमवार सुबह करीब साढ़े छह बजे

उनकी मौत हो गई थी। स्वजन ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाकर करीब साढ़े आठ घंटे तक प्रदर्शन किया था।

सैर पर निकले बुजुर्ग को स्कूटी ने मारी टक्कर, मौत

मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के वर्धमान पुरम रेलवे फाटक के पास सुबह सैर पर निकले एक बुजुर्ग को स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के वर्धमान पुरम रेलवे फाटक के पास सुबह सैर पर निकले एक बुजुर्ग को स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

गोविंदपुरम सिटी पार्क स्थित सूर्या गार्डन के जतिन उपाध्याय का कहना है कि उनके पिता अरविंद कुमार उपाध्याय सात जनवरी की सुबह घर से सुबह की सैर पर निकले थे। इस दौरान जब वह वर्धमान पुरम रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो पीछे से एक युवक तेज रफ्तार में स्कूटी लेकर आया और उन्हें टक्कर मार दी।इस घटना में उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने स्कूटी का नंबर पुलिस को देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर नंबर के आधार पर आरोपित चालक की तलाश की जा रही है।

इनसाइड

स्क्रैप कारोबारी से बदमाशों ने लूटे 44 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस

गाजियाबाद। स्क्रैप कारोबारी से बाइक सवार बदमाश हथियार के बल पर 44 लाख रुपए लूट ले गए। घटना सोमवार देर रात की है। दिल्ली सीलमपुर से व्यापारियों से तगादा कर रूपये लेकर लौट रहे मुरादनगर निवासी स्क्रैप कारोबारी फरमान से बाइक सवार तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर 44 लाख रूपये लूट लिए। वारदात के बाद बदमाशों की बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मौके से गुजर रहे मोरटी निवासी भूपेश से स्कूटी लूटकर फरार हो गए। फरमान अपने दोस्त आसिफ के साथ मुरादनगर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि जानकारी करने पर फरमान ने बताया सोमवार शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली से चले थे। करीब साथ बजे वह राजनगर एक्सटेंशन पहुंचे। जाम की स्थिति को देखते हुए मोरटी कट से भट्टा नंबर पांच की ओर से जाने लगे। कच्चे रास्ते पर पहुंचते से पीछे से आए एक बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। एक बदमाश ने हथियार से चालक की ओर का शीशा तोड़ दिया और पैसे मांगने लगा। वहीं दूसरा बदमाश दूसरी ओर आया और दरवाजा खोलकर आसिफ के घुटने में तमंचे की बट मारी। गोली मारने की धमकी देकर बदमाश पैसों से भरा बैग लूटकर भाग गए। डीसीपी नगर जोन निपुण अग्रवाल ने बताया कि मामले में चार टीम का गठन कर दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

साहब! हम भी इंसान हैं जानवर नहीं, पुलिस रोककर देती है गालियां; ऑटो चालकों ने बयां किया दर्द

अभी धर्मपाल के मामले को देखने दें जबकि आटो चालक अपने प्रश्नों का उत्तर मांगते रहे। कहते रहे कि पुलिसिया उत्पीड़न का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इस मौके पर यदि इस मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी तो कब होगी?

गाजियाबाद। साहब! हम भी इंसान हैं जानवर नहीं। जब और जहां देखो पुलिस हमें रोक लेती है। पेट में डंडा घुसेड़ कर गालियां बकती है। ऑटो पर डंडे बजाती है। अपराधियों को जबरन आटो में बैठाकर अस्पताल व कचहरी ले जाती है। अन्य तमाम बेगारी कराती है। अब तो हमारे साथी की जान तक ले ली। हम अपराधी नहीं हैं बल्कि मेहनत करके अपने परिवार को पालते हैं। हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक क्यों होता है? सोमवार को आटो चालकों ने पुलिसिया उत्पीड़न का दर्द जब पुलिसवालों को सुनाया तो वह निरूत्तर हो गए।

ऑटो चालकों ने साथी धर्मपाल की मौत पर जताया आक्रोश

धर्मपाल की मौत की सूचना मिलने पर दर्जनों आटो चालक सुबह करीब आठ बजे ही शांति गोपाल अस्पताल पहुंच गए। ऑटो चालकों ने साथी धर्मपाल की मौत पर आक्रोश जताया। इस दौरान इंदिरापुरम कोतवाली प्रभारी देवपाल सिंह पुंडीर को घेरकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिसिया उत्पीड़न की पीड़ा सुनाई।

देवपाल सिंह पुंडीर व उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों के पास आटो चालकों के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। उनके सवालों से बचने के लिए पुलिसकर्मियों ने बात घुमा दी। कहा कि यह समय इन बातों की चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे पर बाद में बात की जाएगी।

अभी धर्मपाल के मामले को देखने दें, जबकि आटो चालक अपने प्रश्नों का उत्तर मांगते रहे। कहते रहे कि पुलिसिया उत्पीड़न का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इस मौके पर यदि इस मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी तो कब होगी? बातें नहीं सुनी जाने पर आटो चालकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्हें कठघरे में खड़ा किया।

गुस्से में स्वजन व आटो चालक

धर्मपाल की मौत की सूचना पर दर्जनों आटो चालक सुबह से ही शांति गोपाल अस्पताल पहुंचने लगे। आठ बजते-बजते दर्जनों आटो चालक यहां पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। अस्पताल के गेट में ताला बंद करने की कोशिश की। दोपहर 12 बजे तक सिर्फ इंदिरापुरम कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुंडीर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। अन्य किसी अधिकारी के न आने से स्वजन व आटो चालकों का गुस्सा बढ़ गया।

उन्होंने अस्पताल के पास सीआइएसएफ रोड जाम कर दी। हालांकि पांच मिनट में पुलिस ने उन्हें समझाकर जाम खुलवाया। दोपहर करीब ढाई बजे धर्मपाल की पत्नी व गांव के अन्य लोग पहुंच गए। उनकी पत्नी को रोती देखकर आटो चालक एक भी फिर आक्रोशित हो गए। उन्होंने फिर से सीआइएसएफ रोड पर जाम लगा दिया। करीब 20 मिनट तक रोड जाम रही।

दोपहर करीब तीन बजे पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन डा. दीक्षा शर्मा व सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने स्वजन व आटो चालकों को समझाने की कोशिश की। शाम करीब साढ़े चार बजे उन्हें समझाकर प्रदर्शन समाप्त कराया। प्रदर्शन तो समाप्त हो गया, लेकिन देर रात तक लोग अस्पताल के गेट पर बैठे रहे।

सवारियों को हुई दिक्कत

आटो चालक सुबह करीब आठ बजे से आटो चालकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उनके आटो अस्पताल के आसपास खड़े थे। दर्जनों आटो सड़क पर नहीं चलने से सवारियों को आवाजाही में दिक्कत हुई। तमाम लोग समय से गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए।

जाम से जूझे लोग

शांति गोपाल अस्पताल के सामने, बगल और सीआइएसएफ रोड पर सुबह आठ से शाम करीब पांच बजे तक प्रदर्शन की वजह से आवाजाही प्रभावित रही। रोड जाम के समय तो वाहन चालकों को दिक्कत हुई ही अन्य समय भी यहां वाहनों की रफ्तार धीमी रही। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई।

आटो चालक मुकेश यादव ने कहा कि हम पर तो सिर्फ पुलिस का डंडा चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी इंसान समझना चाहिए।

घटनाक्रम एक नजर में

- रविवार रात 10.00 बजे कनावनी पुश्ता रोड पर आटो व साइकिल में टक्कर

- '' 10.30 बजे पुलिस को मिली सूचना।

10:45 बजे दोनों घायलों को उपचार के लिए शांति गोपाल अस्पाल लाई पुलिस।

- '' 11:15 बजे साइकिल सवार जगतराम को घर भेजा।

हरनंदी नदी के किनारे दो एकड़ में लगाए जाएंगे जंगल

- '' 11:15 बजे आटो चालक धर्मपाल यादव को पुलिस ले गई कनावनी पुलिस चौकी।

- '' 1.00 बजे आटो चालक धर्मपाल यादव के चचेरे भाई मुरारी को फोन करके पुलिस ने चौकी पर बुलाया।

- '' 1:30 बजे मुरारी धर्मपाल यादव को घर लेकर गया।

- '' 3:30 बजे धर्मपाल यादव की तबीयत बिगड़ी।

- सोमवार सुबह 6:00 बजे स्वजन धर्मपाल को लेकर अवंतिका अस्पताल गए।

- 6:30 बजे धर्मपाल को शांति गोपाल अस्पताल लेकर पहुंचे स्वजन। डाक्टरों के मृत घोषित किया।

- '' 8:00 बजे स्वजन व आटो चालकों ने शांति गोपाल अस्पताल के सामने प्रदर्शन शुरू किया।

- सोमवार दोपहर 12:15 बजे सीआइएसएफ रोड जाम की।

- '' 12:20 बजे पुलिस ने जाम खुलवाया।

- '' 2:30 बजे मृतक की पत्नी व अन्य स्वजन गांव से अस्पताल पहुंचे। लोगों ने फिर से सीआइएसएफ रोड जाम की।

- '' 3:00 बजे पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन डा. दीक्षा शर्मा व सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह पहुंचे।

- सोमवार शाम 4.30 बजे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को उचित कार्रवाई व मुआवजा दिलाने का आश्वसन देकर प्रदर्शन समाप्त कराया।

- '' 7:30 बजे स्जवन इंदिरापुरम कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी।

ऑटो एक्सपो 2023: शाहरुख खान की मौजूदगी में हुई ह्यूंडई आईकॉनिक 5 लॉन्च

Auto Expo 2023 भारतीय बाजार में Hyundai ने आधिकारिक तौर पर Ioniq 5 ऑल-इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर को लॉन्च कर दिया है। Hyundai Ioniq 5 भारत में कोरियाई कार निर्माता की किसी भी दूसरी मौजूदा पेशकश की तरह बिल्कुल नहीं दिखती है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Hyundai ने आधिकारिक तौर पर Ioniq 5 ऑल-इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर को लॉन्च कर दिया है। वहीं कीमत की बात करें तो नई Hyundai Ioniq 5 को सिंगल फुली-लोडेड वेरिएंट के लिए 44 .95 लाख रुपये में लॉन्च किया गया है जिसमें यह उपलब्ध होगी। वहीं 21 दिसंबर 2022 से 1 लाख रुपये में पहले से ही बुकिंग खोल दी गई थी। यह कीमत कार के पहले 500 ग्राहकों के लिए लागू है।

कुछ साल पहले प्रदर्शित 45 EV अवधारणा के आधार पर, Hyundai Ioniq 5 भारत में कोरियाई कार निर्माता की किसी भी दूसरी मौजूदा पेशकश की तरह बिल्कुल नहीं दिखती है। Ioniq 5 के इस रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक लुक में नेक्स्ट जनरेशन की डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑल-एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी टेल लैंप्स के लिए एक पिक्सेलेटेड थीम है। इसमें 20-इंच एयरो-ऑप्टिमाइज़्ड एलॉय व्हील शामिल हैं। भारतीय बाजार में ये कार तीन कलर ऑप्शन - ऑप्टिक व्हाइट, ग्रेविटी गोल्ड मैट और मिडनाइट ब्लैक पर्ल में उपलब्ध है।

इनसाइड

घर में ईवी चार्जर कैसे करें इंस्टाल? आसान भाषा में समझें स्टेप बॉय स्टेप तरीका

इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट इंस्टाल होने के बाद आप आप अपनी ईवी चार्ज कर सकते हैं। हालांकि घर पर चार्जिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए जैसे कि तुरंत गाड़ी को धुलने के बाद उसे चार्जिंग में लगाने से बचना चाहिए नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है।

नई दिल्ली। यदि आप इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के मालिक हैं और आपको अपने व्हीकल को चार्ज करने में समस्या आ रही है तो आप इसे अपने घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। घर में ईवी चार्जर को कैसे इंस्टाल करना होगा उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नीचे दी जा रही है।

अगर आपका एक ही परिवार है और आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको लेवल 2 चार्जर की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई प्रकार के चार्जर हैं। हालांकि, यदि आप इसे अपने निजी वाहन के लिए यूज करते हैं तो लेवल 2 से आपका काम बन जाएगा। ईवी चार्जर को इंस्टाल करने के लिए सबसे पहले एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन हायर करें। ताकि वह आपके घर के बनावट और वायरिंग इंफ्रा को देखकर सही जगह को बता सके। काम ठीक से और सुरक्षित रूप से करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के बुनियादी ढांचे के बारे में ज्ञान रखने वाले एक प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन को काम पर रखना उचित है। यह आपके घर और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट इंस्टाल होने के बाद आप आप अपनी ईवी चार्ज कर सकते हैं। हालांकि, घर पर चार्जिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि तुरंत गाड़ी को धुलने के बाद उसे चार्जिंग में लगाने से बचना चाहिए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है।

इन स्टेप को फॉलो करके घर पर ही बनाएं ईवी चार्जिंग प्वाइंट

Step 1 : इलेक्ट्रिशियन को हायर करें

Step 2 : परमिशन लें

Step 3 : सही जगह ढूढें

Step 4 : लेवल 2 चार्जर को खरीदें

Step 5 : चार्जर को इंस्टॉल करवाएं

मारुति की EVX एसयूवी से उठा पर्दा, फुल चार्ज में 550 KM रेंज का दावा

यात्री वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी एक्स एसयूवी के वैश्विक अनावरण के साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की सबसे बड़ी आठ दिवसीय द्विवर्षीय प्रदर्शनी- द ऑटो एक्सपो – मोटर शो 2023आज से शुरू हो गई। इस शो में कंपनियां ई मोबिलिटी पर ध्यान केनद्रित कर रही है । इसमें न सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और उसके कल पुर्जे बल्कि इलेक्ट्रिक कारें और स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) के नये मॉडल और कान्सेपट मॉडलो का प्रदर्शन किया जा रहा है।

मारुति की ई एसयूवी एक बार चार्ज होने पर 550 किलोमीटर चलेगी। कंपनी वर्ष 2025 में ई वाहन लांच करने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। प्रतिनिधि निदेशक और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तोशिहीरो सुजुकी ने इस एसयूवी का अनावरण किया। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 12 जनवरी 2023 को होगा। पहले और दूसरे दिन अर्थात 11 जनवरी और 12 जनवरी को यह शो विशेष रूप से मीडिया के लिए होगा। इसके बाद तीसरे दिन 13 जनवरी को यह सिर्फ बिजनेस विजिटरों के लिए होगा और उसके बाद 14 जनवरी से 18 जनवरी तक यह शो आम आदमी के लिए खुलेगा।

ऑटोमोटिव कॉम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एक्मा) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा प्रदर्शनी के इस 16वें संस्करण की थीम 'गतिशीलता की दुनिया की खोज' ('एक्स्प्लोर द वर्ल्ड ऑफ़ मोबिलिटी') है। यह थीम उद्योग की एक ज्यादा सुरक्षित, स्वच्छ, हरे-भरे और जुड़े हुए भविष्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल दूरदर्शी सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से मेल खाती है। यह प्रदर्शनी दर्शकों को बदलते और क्रमिक रूप से विकसित होते मोबिलिटी इकोसिस्टम की समझ प्रदान करेगी और भविष्य के लिए तत्पर नए-नए तथा बेहतर समाधान पेश करेगी।

National Road Safety Week 2023: एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले करें ये काम

रोड एक्सीडेंट कई तरह से होते हैं जिनके कारण भी भिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन अधिकतर मामले तेज गति और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते होता है। ऐसे में आपको रोड पर कार चलाते समय काफी सतर्क रहना चाहिए ताकि आप सतर्कता से अपने आप को बचा सके।

नई दिल्ली। आय दिन भारत में सड़क हादसे होते हैं। जिसके कारण कई लोगों की मौत और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। दिन पर दिन बढ़ते ट्रैफिक के चलते सड़कों पर होने वाले हादसों के शिकार की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल के दिनो में भारत के मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उनको काफी चोट लगी है। उस समय ऋषभ पंत ने खुद को अपनी सूझबूझ से बचा लिया था । आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसे जानकर आप हादसों को टालने और एक्सीडेंट की स्थिति में बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

कार को स्टार्ट करने की कोशिश न करें

अगर आपकी कार पलट गई हो तो कार को स्टार्ट करने की कोशिश न करें। उसे सीधे वर्कशॉप ही भेजें। कार के पलटने के दौरान इंजन ऑयल सहित कई फ्लूइड्स बाहर आ जाते हैं। ऐसे में आप कार को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो इंजन में खराबी आ सकती है। वहीं डीजल लीक होने की स्थिति में आग भी कार पकड़ सकती है।

कार में आग लगे तो क्या करें

कभी भी आपके कार से उठते धुंए को नजरअंदाज न करें क्योंकि ये आपके कार में किसी न किसी बड़ी खराबी को संकेत करता है। कई बार डीजल पेट्रोल के इंजेक्टर से लीक होने या फिर फिल्टर से लीक होने और कार इंजन गर्म होने के चलते ऐसा धुआं दिखने लगता है। ऐसे में कार को किनारे कर तुरंत बंद कर दे। इसके बाद टायर के पास ये देखें कि इंजन में लपटे तो नहीं दिख रही है। यदि कार इंजन में लपटें दिखती हैं तो इसे न खोलें और फायर ब्रिगेड या एक्सटिंग्विशर का इंतजाम कर स्प्रे करें।

तेज स्पीड के कारण एक्सीडेंट हो तो करें ये काम

अगर आपका एक्सीडेंट तेज स्पीड में होता है तो कार में एयरबैग पहले से खुल जाते हैं। जिसके कारण आपके बचने के चांस हो जाते हैं। इसके बाद आपको जल्द से जल्द कार से बाहर निकल जाना चहिए। कार को हो सके तो सड़क के किनारे करें जिससे आस -पास के यातायात को कोई परेशानी न हो । आप आपातकालीन सहायता को फोन करें और पुलिस को भी सूचित करें। अगर आपकी कार से डीजल और पेट्रोल लीक हो रहा है तो उस जगह पर मिट्टी डालें। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि कार के बोनट को खोलने की कोशिश न करें क्योंकि इस दौरान कई बार कूलेंट और डिस्टिल वाटर प्रैशर के साथ बाहर निकल सकता है जो काफी गर्म होता है।

अगर कार पानी में गिर जाएं तो ऐसे निकाले

आपको बता दे कई बार कार हादसे के दौरान कार तालाब , नदी या नाले में गिर जाती है। ऐसे समय में पानी के प्रेशर के चलते हुए कार का गेट खुल नहीं पाता है। जिसके कारण कार में बैठे लोग फंसने के चलते हादसे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन सभी वाहन निर्माता कंपनियां ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इक्विपमेंट हर कार में देती है। ऐसी स्थिति में आप कार के हैडरेस्ट को निकालें। आपने ये देखा होगा कि कार के हेड रेस्ट की रॉड का छोर तिकोना होता है। इससे कार के शीशे पर चोट करें तो तत्काल ये टूट जाएगा और खिड़की के जरिए कार से बाहर निकल सकते हैं।

विवेकानंद के उपदेशों की अनिवार्यता

प्रियंवदा

सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है, अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है।' स्वामी विवेकानंद केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे'.

भारत देश को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से परिचय करवाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को तत्कालीन कलकत्ता में एक प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी के घर हुआ। बचपन में नरेंद्र नाथ या नरेन के नाम से जाने जाते थे। बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी नरेंद्र के व्यवहार और वक्तृता से उनके सहपाठी ही नहीं अध्यापक भी प्रभावित रहते थे। विवेकानंद जी के समकालीन रहे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था : 'यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढिए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं।' आज का युवा वर्ग भी उनके उपदेशों को पढ़े, जाने और समझे तो निश्चित रूप से सफलता की सीढियां चढ़ सकता है।

वर्तमान समय में टेलीविजन, मोबाइल के अतिरिक्त और भी कितनी ही आधुनिक तकनीकें आसानी से उपलब्ध हो जाती है जो चंचल मनोवृत्ति वाले युवाओं को पथभ्रष्ट करने में कारगर साबित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक, बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण पीएचडी या उच्च योग्यता संपन्न युवा जब न्यूनतम वेतन पाकर हताशा और निराशा की गिरफ्त से गुजरते हैं या बेरोजगारी का दंश झेल कर सडक़ों पर भटकते हैं और नैतिक शिक्षा को धत्ता बता वे दुव्यसनों की ओर आकर्षित होकर, झूठ बोलकर या गलत तरीके अपना कर पैसे कमाने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। जाने-अनजाने एक बुराई उनके भीतर पनपने लगती है। जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाजसेवा की भावना विकसित नहीं करती, जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ? स्वामी विवेकानंद जी अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और गहन वैदिक ज्ञान के कारण भारतीयों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। शिक्षा के संदर्भ में उनके विचार थे : 'हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके।' 19वीं सदी में रामकृष्ण परमहंस जी के प्रमुख शिष्य रहे विवेकानंद जी ने अपने गुरू के नाम पर रामकृष्ण मिशन का गठन 1 मई 1897 में किया। आध्यात्मिकता से अधिक लौकिक जगत को महत्व देने वाले विवेकानंद का मानना था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति पहले भारत पुत्र है, फिर किसी धर्म का पुत्र है। वे राष्ट्रीयता के पोषक थे, इसलिए उन्होंने नवयुवकों को प्रेरित करते हुए कहा : 'उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ।

अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।' आज हमारे समाज में हमारी युवा पीढ़ी जिस प्रकार लिव-इन-रिलेशनशिप की ओर लगातार बढ़ रही है वह निंदनीय तो है ही, इससे भी अधिक सोचनीय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? युवाओं को विवेकानंद जी के जीवन के उस प्रसंग से सीखना चाहिए कि जब एक अमेरिकी युवती उनके रूप और प्रभावशाली व्यक्तित्व पर मोहित होकर उनसे शादी करने की पेशकश ये कहकर करती है कि वह उनके जैसा सुशील, गौरवशाली, तेजयुक्त व गुणवान पुत्र पाना चाहती है तो स्वामी जी का उत्तर था कि, 'ऐसा तो बिना शादी के भी संभव है कि मैं स्वयं आपका पुत्र बन जाता हूं और आप मेरी मां बन जाएं।' इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण में उनकी पोशाक को लेकर जब विदेशी महिलाओं ने तंज कसा तो उनका उत्तर था कि, 'महोदया, आपके देश में एक दर्जी है जो आदमी को सज्जन बनाता है, लेकिन जिस देश से मैं आता हूं वहां चरित्र है जो आदमी को सज्जन बनाता है।' स्वामी जी ने भारतीयों के चरित्र की जो गरिमा विदेशों में जाकर बनाई है वह प्रत्येक देशवासी को अनुकरणीय है। मनुष्य को अपने जीवन में कुछ नया करने में अक्सर तीन स्थितियों से दो-चार होना पड़ता है, व्यक्ति सबसे पहले उपहास का पात्र बन जाता है, फिर उसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है। बाद में उसे समाज स्वीकृति भी दे देता है। व्यक्ति को परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जो कार्य वह समाज हित या राष्ट्र हित के लिए कर रहा है उसे मजबूत आत्मबल के साथ करेगा तो अवश्य ही सफल होगा। विवेकानंद जी का मानना था कि हमें कार्य पूरी लगन और शिद्दत के साथ करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के वक्तव्य में गजब की आकर्षण शक्ति थी। किसी चुम्बकीय शक्ति से लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे।

यह उनकी कठिन तपस्या और अच्छे लोगों की संगत का ही परिणाम था जो उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट झलकता था। 'दूसरों के पीछे भागने की बजाय अपना लक्ष्य खुद बनाओ।' स्वामी विवेकानंद जी का यह उपदेश भी वर्तमान समय में उन युवाओं को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त है। दूसरों की देखा-देखी न केवल अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं बल्कि उनकी गति भी अवरुद्ध हो जाती है। 4 जुलाई 1902 को इस लौकिक संसार को छोडक़र केवल 39 वर्ष की आयु में समाधि लेने वाले स्वामी जी ने कहा, 'अभय-निडर रहो। अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है, हर तरह की दुर्बलता से बचो, दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है, कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो। सत्य मजबूत बनाता है। सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है, अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है।' स्वामी विवेकानंद केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे जिनकी शिक्षा और विचार आज भी ग्रहण करने योग्य हैं। इनसे प्रत्येक युवक को सीख लेकर अपने जीवन में उतारना श्रेयस्कर रहेगा।

संपादक की कलम से

कई और जोशीमठ भी हैं

उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में जो दिख रहा है, वह कई तरह के आपातकाल और विध्वंसकाल की चेतावनी है। भू-स्खलन हो रहा है। ग्लेशियर पिघल कर स्थान बदल रहे हैं और मलबे-मिट्टी के पहाड़ों पर शहर बसे हैं। ज़िंदगी और दुनिया आबाद है, लेकिन अब लोग बेघर हो रहे हैं। जोशीमठ में 678 घर खतरनाक स्थिति में हैं, लिहाजा खाली कराए जा रहे हैं। अभी तक 81 मकान खाली कराए जा चुके हैं, सिलसिला जारी है और उनमें रहने वालों को शिफ्ट किया जा रहा है। ज़िंदगी विस्थापित हो रही है। यह अनुभव चार दशक पहले भी भयावह और असुरक्षित था और आज भी त्रासदी के मुहाने पर है। तब भू-वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने जो रपटें सरकार को दी थीं, वे कहीं धूल फांक रही होंगी, क्योंकि निर्माण, बुनियादी ढांचे, सुरंगें, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल लाइन आदि के जरिए विकास के बिम्ब उभारना सरकार की योजनाओं में शामिल था।

बीते कुछ अंतराल में गढ़वाल हिमालय में जो आर्थिक और मानवीय नुकसान सामने आए हैं, उनसे साफ हो गया था कि ऐसे विकास में सरकार को पर्यावरण संबंधी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जीडीपी का भारी पतन होगा, लेकिन पहाड़ों का छलनी किया जाना, विस्फोटों से सुरंग बनाना, पहाड़ को क्षत-विक्षत कर रेलवे लाइन बिछाना और पनबिजली तथा खनन माफिया की मुनाफाखोरी जारी रही। आज खौफनाक मंजर सामने दिख रहा है। जोशीमठ का महत्त्व सांस्कृतिक, पौराणिक, आध्यात्मिक और सामरिक है। सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सीमा है। इसे भगवान विष्णु का दूसरा घर माना जाता था। आदि शंकराचार्य ने भारत में हिंदुत्व के जो चार मठ स्थापित किए थे, उनमें से एक 'ज्योतिर्मठ' इसी शहर का प्राचीन नाम था। विष्णु अवतार नरसिंह भगवान भी अपना गुस्सा शांत करने इसी पहाड़ पर आए थे। लोग उनके मंदिर में पूजा करते हैं। आज शिवलिंग भी खंडित हो गया है, लिहाजा श्रद्धालु उसे देखकर रो रहे हैं और किसी अनिष्ट की कल्पना से कांप रहे हैं।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने खाली हो चुके और दरारों से फटे मकानों को ध्वस्त करने के आदेश भी दे दिए हैं। जो आशियाने थे, वे अब मलबा हो जाएंगे। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, राज्य के अन्य 70 स्थानों और गांवों के लोगों ने भी घरों, ज़मीन में दरारों की शिकायतें की हैं। टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमौली जिलों के हालात भी जोशीमठ सरीखे हो सकते हैं। वहां भी पहाड़ को छिन्न-भिन्न किया गया है। कुल 35,000 परिवारों पर अचानक संकट आ पसरा है। किस-किस पहाड़ी स्थल को ध्वस्त करेंगे, खाली कराएंगे और मलबे-मिट्टी में तबदील होता देखते रहेंगे? कमोबेश सभी पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है। पहाड़ों पर अप्रत्याशित, अवांछित बोझ है। विकास के नाम पर पहाड़ों को चीर-चीर कर 'महानगरीय' बनाने की भूख पहाड़ों को ज़िंदा कहां रहने देगी? दरअसल 'ग्लोबल क्लाईमेट रिस्क इंडेक्स, 2020' में भारत का स्थान पांचवां है। इससे भारत बेहद असुरक्षित और आघात-योग्य देशों की जमात में आ गया है। तब भयभीत होकर भारत सरकार ने 2070 तक 'शून्य कार्बन उत्सर्जन' का लक्ष्य घोषित किया है। यानी सरकार जलवायु परिवर्तन के खतरे भांप और आंक रही है। नीति आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरीखे संवैधानिक संगठन अपनी-अपनी रपटों में आगाह कर चुके हैं कि पहाड़ों पर जो अतिक्रमण, ड्रिल निर्माण किए जा रहे हैं, विकास के नाम पर सुरंगें और राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, उनके कारण एक दिन पहाड़ पर जीवन ही समाप्त हो सकता है। इससे बड़ी और खौफनाक चेतावनी और क्या हो सकती है?

12 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष देश 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। विवेकानंद संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे।

वह वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया का परिचय कराने वाली प्रमुख हस्ती थे। उन्हें 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को दुनिया के प्रमुख धर्मों में स्थान दिलाने का श्रेय जाता है। उन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।

शिकागो में दिया था यादगार भाषण

विवेकानंद को 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण की वजह से सबसे ज्यादा याद किया जाता है। दुनिया भर के धार्मिक नेताओं की मौजूदगी में जब विवेकानंद ने, "अमेरिकी बहनों और भाइयों" के साथ जो संबोधन शुरू किया तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। इस धर्म संसद में उन्होंने जिस अंदाज में हिंदू धर्म का परिचय दुनिया से कराया, उससे वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए।

रामकृष्ण परमहंस थे विवेकानंद के गुरु

स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म की ओर था। 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई और वही उनके गुरु बन गए। अपने गुरु रामकृष्ण से प्रभावित होकर उन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया था।

स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके एक साल बाद उन्होंने गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की।

04 जुलाई 1902 को महज 39 वर्ष की अल्पायु में विवेकानंद का बेलूर मठ में निधन हो गया था।

राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है विवेकानंद का जन्मदिन

1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन (12 जनवरी) को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था और 1985 से हर वर्ष विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बंद दफ्तरों के आगे

हिमाचल में पिछली सरकार के अंतिम चरण के फैसलों को वर्तमान की चुनौती में देखना जितना आवश्यक है, उतना ही लाजिमी है अर्थ गणित में प्रदेश की प्राथमिकताओं को गतिशील बनाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की मानें तो पिछली जयराम सरकार ने तीन हजार करोड़ की होली खेलते हुए, अपने रिवाज बदलने की कोशिश में आर्थिक स्थिति का मुंडन कर दिया। करीब 590 कार्यालयों की फेहरिस्त में अब जवाबदेही ढूंढने का वक्त आया, तो इसे केवल राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही क्यों समझा जाए। यह भी मानना पड़ेगा कि नए संस्थानों की अंधी बारिश के बावजूद न कभी मिशन रिपीट हुआ और न ही इस बार रिवाज बदलने का संकल्प पूरा हुआ। भले ही विपक्ष कार्यालयों के डिनोटिफाइड होने को लेकर राज्यपाल तक पहुंच गया या आने वाले समय में इसको लेकर अदालती मंचन भी करे, लेकिन कहीं तो प्रदेश के लिए हमें सोचना ही पड़ेगा और इस बार यह दायित्व कांग्रेस सरकार का है। बात केवल 590 कार्यालयों के खोलने पर किए गए एतराज तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे यह फैसला लेने की दृढ़ता से पता चलेगा कि जनता को असली संदेश है क्या। सरकार को अगर वित्तीय अनुशासन कामयाब करना है, तो आरंभिक तौर पर पिछली सरकार के फैसले पलटना आसान होगा, मगर यह सवाल नीति-निर्देशों की बानगी में भी देखा जाएगा, ताकि पता चले कि सुक्खू सरकार अपने तौर पर कितनी किफायत से प्रदेश को बचा रही है। यह सत्ता के लाभार्थी पदों पर नई नियुक्तियों, कार्यालयों के युक्तिकरण, अनावश्यक कार्यालयों पर कार्रवाई तथा विकास के समन्वय व प्रादेशिक संतुलन से ही सामने आएगा।

प्रदेश में सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को प्रदर्शित करते सरकार के इरादे कार्य संस्कृति को कितना सशक्त करते हैं या सरकारी मशीनरी कितनी अनुशासित हो पाती है, यह देखना होगा। नई सरकार के लिए अपने पांव जमाने और कुछ नया कर दिखाने की भले ही चुनावी शर्तें सबसे पहले सामने आ रही हैं, लेकिन स्थायी तौर पर इंस्टीच्यूट बिल्डिंग तथा संस्थानों व कार्यालयों के दायित्व निर्वहन में गुणवत्ता लाने की सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल कार्यालयों की डिनोटिफिकेशन के तर्क कई अधूरे संकल्पों, अतार्किक फैसलों तथा राजनीतिक अनैतिकता की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में क्या वर्तमान सरकार उन तमाम कार्यालयों, संस्थानों, भवनों, विभागों, निगमों व बोर्डों को भी बंद करेगी, जो निरंतर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ही कमजोर कर रहे हैं। सरकारों के अनावश्यक नखरे तो समारोहों के आयोजन तथा सत्ता की परिपाटियों में भी नजर आते हैं, तो क्या हम समझें कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो अनावश्यक है। सरकार के कठोर फैसलों का स्वागत करने वालों की एक सूची है और इस लिहाज से, मंतव्य को जाहिर करने की ईमानदारी अगर सामने आती है, तो यह सोने पे सुहागा ही होगा। सरकार अगर एक नई परिपाटी के तहत फैसले लेने का सामथ्र्य रखती है, तो एक बार पिछली तमाम सरकारों के मंतव्य और गंतव्य को भी समझ लेना होगा, क्योंकि अब कई बदलाव आ चुके हैं और भविष्य की चुनौतियां भी सख्त हो रही हैं। सरकार को पिछली भाजपा सरकार की 'डबल इंजन' अवधारणा का जवाब खोजना है और साबित भी करना है कि राज्य अपने बूते स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, कार्यप्रणाली और अपने आर्थिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। पहली डगर पर सबसे अहम होगा कि सुशासन की परिपाटी में अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और फिजूल खर्चियों से हटकर भविष्य के रास्ते खोजे जाएं।

बनने-बनाने में सोई सरकार

इधर लोग असमंजस में हैं कि सरकार बनने-बनाने के बीच कहाँ सो गई। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार बन गई है, लेकिन कहीं नजऱ नहीं आ रही। पर, सरकार का दावा है कि सरकार दिन ही नहीं, रात के अँधेरे में भी उल्लू की तरह देखने पर खुली आँखों से देखी जा सकती है। अगर यक़ीन न हो, तो उन लोगों से पूछ कर देख लो जो पूर्व सरकार की अधिसूचनाओं को निरस्त किए जाने के बाद घर बैठ कर ऐडियाँ सहला रहे हैं। अगर फिर भी कोई शक-शुबहा बाक़ी रहे तो प्रदेश में चलते उन जन आन्दोलनों को देख लें जिसमें पूर्व सरकार द्वारा गठित नए उपमंडलों, तहसीलों, विकास खंडों या कार्यालयों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। विपक्ष का दावा है कि नई सरकार का ट्रेलर, जिसमें बारह पहिए होने चाहिए थे, केवल दो पहियों पर रगड़-घिसट कर चल रहा है।

सरकार कहती है कि विपक्ष कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देख ले। उसके ट्रेलर में भले बारह पहिए थे, पर सभी अलग-अलग दिशाओं में घूम रहे थे। लोगों को कौन समझाए कि सरकार का काम तो घूमना ही है, चाहे आगे घूमे या पीछे। दाएं घूमे या बाएं। अगर ऐसा न होता तो देश आगे कैसे बढ़ता, तरक्की कैसे करता। फिर चुनावी मेनिफेस्टो में न तो सत्ताधारी दल कहीं कहता है कि सरकार आगे चलेगी या पीछे, दाएं चलेगी या बाएं और न विपक्ष। इसमें तो केवल सब्ज़बाग़ दिखाए जाते हैं। उन्हें न तो जन पढ़ता है, न गण और न मन। ऐसे में उसमें किए गए अनर्गल प्रलाप को पढने की ज़हमत वह नई गठित सरकार क्यों उठाए, जिसे ढोने के लिए लोगों ने पाँच साल के लिए अपने कँधे उधार दिए हों। सरकारें तो नारों पर ही चलती हैं, मसलन 'अच्छे दिन आने वाले है', 'सबका साथ, सबका विकास', 'ग़रीबी हटाओ, देश बचाओ', 'शिक्षा की उड़ान', 'शिक्षा पर सबका अधिकार', 'रोटी कपड़ा और मकान', 'शिक्षा से बनेगा देश महान', 'बेटी पढ़ाओ देश बचाओ' वग़ैरह-वगऱैह। इतिहास का पता नहीं पर समय गवाह है कि देश में अच्छे दिन आ चुके हैं, ग़रीबी हटने से देश सुरक्षित है, सबके साथ सबका विकास हो रहा है, शिक्षा पर सबके अधिकार से देश ऊँची उड़ान पर है, लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं और ब्रैंडेड कपड़े पहन कर अमूल मक्खन के साथ रोटियाँ खा रहे हैं, बेटियाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं और आप चाहें तो रात को बाहर पत्नी, बहिन या बेटी के साथ अँधेरी गलियों में बेख़ौफ घूम सकते हैं। अगर कुछ ऊँच-नीच हो जाए तो गाँधारी बनी न्याय की देवी एकतरफा झुके तराजू के साथ आपकी सेवा में हाजिऱ है।

लेकिन लोगों के हर बार बनने से लगता है कि उन्हें सियासी अय्यारी को भाँपने का हुनर नहीं आता, जबकि बुज़ुर्ग कहते हैं कि घर में नई-नवेली दुल्हन के पहला क़दम रखते ही उसके स्वभाव, बर्ताव और निभाई का पता चल जाता है। दरअसल लोगों को भले बनाना न आता हो, बनना अवश्य आता है और हर बार बनने के बाद जब तक जागते हैं तो देर हो जाती है। ग़लती सुधारने के लिए अगली बार वोट डालने और नई सरकार चुनने के बाद, उन्हें फिर पता लगता है कि दोबारा बन गए। पर जो मज़ा बनने में है, वह बनाने में नहीं। इसीलिए लोग हर बार बनना ही पसन्द करते हैं। हाल-फ़िलहाल में ही देख लो। राजधानी में सत्ताई गलियारे सूनी पड़े हैं। मानो अघोषित धारा 144 लागू हो। लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि चुनावी आचार संहिता उठा ली गई है या लागू है। बेचारे नियमित होने वाले अनुबंधित सरकारी कर्मी अवधि पूरी होने के बावजूद महीनों से इन्तज़ार में है कि नए मंत्री कुरसी पर विराजें तो नियुक्ति-पत्र मिले। लेकिन शायद उनसे ज़्यादा बुरी हालत चुनाव जीते उन विधायकों की है जो सरकार बनने के बाद बेरोजग़ार घूम रहे हैं और कुछ पाने की चाहत में सरकार पर होने वाले विपक्षी हमलों को अपनी नंगी छाती पर झेल रहे हैं।

पी. ए. सिद्धार्थ

परीक्षा-मूल्यांकन की विश्वसनीयता पर सवाल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सिफारिश पर जब विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपनाया तब ग्रेड सिस्टम शुरू किया गया। अपनाई गई यह प्रणाली मूलत: शारदा विश्वविद्यालय की प्रणाली की ही प्रतिकृति थी जिसमें 7 श्रेणियां रखी गई थीं, लेकिन उस व्यवस्था की एक अनिवार्यता यह थी...

हिमाचल प्रदेश के महविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में इन दिनों एक अलग तरह का रोष विश्वविद्यालय के प्रति पनप रहा है और यह रोष है 'उत्तीर्णता का कम प्रतिशत'। इस वर्ष बहुत ही कम विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो पाए हैं यानी 'पास पर्सेंटेज' बहुत ही कम रहा। कारण जो भी रहे हों लेकिन विद्यार्थियों को आंदोलन का एक ज्वलंत मुद्दा मिल गया है। हाल ही में विधानसभा चुनाव का दौर समाप्त हुआ है जिसमें युवाओं का जोश अपने चरम पर था, चुनावी माहौल के शांत होते ही अपेक्षाकृत संगठित छात्रशक्ति को यह नया मुद्दा अपनी भड़ास निकालने के लिए मिल गया। आए दिन छात्र अपने-अपने महाविद्यालय के प्राचार्यों के माध्यम से प्रदेश विश्वविद्यालय एवं सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर नारेबाजी करते हैं जिससे महाविद्यालयों में शिक्षा का वातावरण प्रभावित हो रहा है। सबसे अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि विश्वविद्यालय इतनी कम उत्तीर्णता प्रतिशत वाले परीक्षा परिणाम को बिना तुलनात्मक अध्ययन (कोलेशन) के कैसे घोषित कर सकता है, क्योंकि परीक्षा परिणाम घोषित करने से पहले एक तुलनात्मक सारणी बनती है जिसमें विगत वर्षों के परिणामों से वर्तमान परिणाम की तुलना की जाती है। यदि वर्तमान परिणाम प्रतिशत का अंतर विगत वर्षों के परिणाम प्रतिशत से 10 फीसदी से अधिक पाया जाता है तो उसका पुनर्विलोकन किया जाता है और फिर माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति के उपरांत ही परिणाम घोषित किया जाता है। अधिक अंतर होने पर इस अंतर का औचित्य प्रमाणित करना पड़ता है। विश्वविद्यालय स्तर पर कुछ तो कोताही हुई है जिसके कारण छात्र आंदोलित हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सिफारिश पर जब विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपनाया तब ग्रेड सिस्टम शुरू किया गया। अपनाई गई यह प्रणाली मूलतः शारदा विश्वविद्यालय की प्रणाली की ही प्रतिकृति थी जिसमें 7 श्रेणियां रखी गई थीं, लेकिन उस व्यवस्था की एक अनिवार्यता यह थी कि किसी भी कक्षा के सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम एक साथ ही आ जाना चाहिए (जो प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए असंभव सी बात है), किसी कक्षा का एक भी परिणाम विलंब से घोषित होने से सारी ग्रेड व्यवस्था ही बाधित/परिवर्तित हो जाती है। इस व्यवस्था में अधिकतम अर्जित अंकों को 100 व न्यूनतम अंकों को 0 मानकर सारे परिणाम को युक्तिकृत किया जाता है, 0 और 100 के मध्य के अंकों को यानी कि 50 अंकों को मध्यिका (मेडन) लेकर उसके आगे-पीछे के 3 मानक विचलन (स्टैंडर्ड डिवाइएशन) को लेकर उत्तीर्णता की ग्रेड/श्रेणियां बनती हैं (जैसे कि मध्यिका प्लस 1, मध्यिका प्लस 2, मध्यिका प्लस 3, मध्यिका, मध्यिका माइनस 1, मध्यिका माइनस 2, मध्यिका माइनस 3, ये सात ग्रेड/श्रेणियां बनती हैं)। यह वर्गीकरण इतना तर्कसंगत है कि इसमें उत्तीर्णता के प्रतिशत का प्रश्न बेमानी हो जाता है क्योंकि हर परीक्षार्थी को कोई न कोई ग्रेड मिलता है चाहे वह उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण। कक्षा के सभी परीक्षार्थियों के परिणाम के आधार पर ही ग्रेडिंग होती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल जो परसेंटाइल का चलन शुरू हुआ है उसी का एक स्वरूप यह ग्रेड सिस्टम है।

जब विश्वविद्यालय ने इस पद्धति को अपना लिया तो उससे विमुख होने के पीछे कोई कारण नहीं दिखता है और बिना कारण के विद्यार्थियों के साथ इस तरह के प्रयोग करके उनके भविष्य की अनदेखी करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। किसी भी नई व्यवस्था/प्रक्रिया को अपनाने से पहले इसका ठीक से ट्रायल कर के यानी कि पायलट करके इसके सभी पहलुओं को, गुण-दोष विचार कर यह सुनिश्चित कर लेना अति आवश्यक हो जाता है कि इस प्रणाली को अपनाने में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है ताकि समय रहते इसे संशोधित किया जा सके। हाल की समस्या का एक कारण जो विद्यार्थी उद्धृत करते हैं वह यह कि विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन से परिणाम तैयार करने तक की सारी प्रक्रिया की ही आउटसोर्सिंग कर दी है यानी किसी बाहरी स्रोत को ठेके पर दे दिया है, लेकिन ऐसा करना तभी सही होगा जब समानांतर रूप से प्रचलित प्रक्रिया को भी जारी रखा जाए। यदि दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम में अंतर नगण्य या न्यूनतम है, तभी नई प्रक्रिया को उचित व अनिवार्य शोधन के उपरांत ही अपनाना चाहिए। 2012-13 में भी इस तरह का प्रयोग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किया गया था जब इंटीग्रेटिड एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम (आईईएमएस) अपनाने के लिए पायलट के रूप में बी. कॉम. अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन व उसके उपरांत की परिणाम तैयार करने तक की सारी प्रक्रिया को कम्प्यूटर के प्रयोग से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा ही सम्पन्न किया गया था।

इनसाइड

लिस्टिंग से पहले उछला GMP, आनलाइन चेक करें अलाटमेंट स्टेटस

DCX IPO Allotment Status DCX Systems IPO का आज अलॉटमेंट किया जा रहा है। ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी उछाल पर है। BSE वेबसाइट पर लॉग इन करके इसकी ऑनलाइन जांच की जा सकती है। अगर आपने अप्लाई किया है तो स्टेटस चेक कर लें।

नई दिल्ली। DCX Systems Limited के IPO शेयर आवंटन की घोषणा आज होने की संभावना है। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक तीन दिनों की बोली के दौरान निवेशकों ने DCX Systems IPO के प्रति खासा उत्साह दिखाया है। ग्रे मार्केट में 500 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू पर तेजी पर बना हुआ है। डीसीएक्स सिस्टम्स के आईपीओ का जीएमपी 78 है। सुबह के सत्र में यह 75 के स्तर पर था।

DCX सिस्टम्स IPO GMP

बाजार पर्यवेक्षकों के अनुसार, DCX सिस्टम्स IPO GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) आज 78 है, जो कल के GMP 75 प्रति इक्विटी शेयर से 3 रुपये अधिक है। पिछले दो दिनों से DCX सिस्टम्स के शेयर की कीमत ग्रे मार्केट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

DCX सिस्टम्स IPO: आनलाइन जांच कैसे करें

जिन लोगों ने 500 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन किया है, वे बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट bseindia.com या आईपीओ के आधिकारिक रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने आवेदन की स्थिति की आनलाइन जांच कर सकते हैं।

DCX सिस्टम्स IPO के लिए नियुक्त आधिकारिक रजिस्ट्रार Link Intime Private Limited है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट linkintime.co.in है। शेयर आवंटन की घोषणा के बाद बोलीदाता इन वेबसाइटों पर अपने आईपीओ आवेदन की स्थिति की आनलाइन जांच कर सकते हैं।

ये है तरीका

बीएसई के लिंक bseindia.com/investors/appli_check.aspx या सीधे लिंक इनटाइम वेब लिंक linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html पर लॉगिन कर शेयरों की जांच की जा सकती है।

बीएसई लिंक पर लॉग इन करें- bseindia.com/investors/appli_check.aspx;

डीसीएक्स सिस्टम्स आईपीओ चुनें

डीसीएक्स सिस्टम्स आईपीओ आवेदन संख्या दर्ज करें

अपना पैन डिटेल दर्ज करें

'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें

'सबमिट' बटन पर क्लिक करें

आपकी DCX सिस्टम्स IPO आवंटन स्थिति कंप्यूटर मॉनीटर या स्मार्टफोन स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी

डायरेक्ट इनटाइम लिंक

शेयर आवंटन की घोषणा के बाद, बोलीदाता सीधे लिंक इनटाइम वेब लिंक linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html पर लॉग इन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका यह है।

डायरेक्ट लिंक इनटाइम वेब लिंक पर लॉग इन करें- linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html;

डीसीएक्स सिस्टम्स आईपीओ चुनें

अपना पैन नंबर दर्ज करें

'सर्च' विकल्प पर क्लिक करें

आपकी DCX सिस्टम्स IPO आवंटन स्थिति कंप्यूटर मॉनीटर या स्मार्टफोन स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी।

दौलत गंवाने का वर्ल्ड रिकार्ड, एक साल में 180 अरब डालर खो चुके हैं एलन मस्क

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी व टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के मालिक एलन मस्क बीते साल सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले शख्स हैं, जिन्होंने साल की शुरुआत दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में की थी। लेकिन अब उन्होंने लगातार कम होती संपत्ति के कारण सबसे ज्यादा निजी संपत्ति गंवाने वाले शख्स के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार एलन मस्क को नवंबर 2021 से अब तक लगभग 182 अरब डालर का नुकसान हुआ है। फोब्र्स के अनुसार मस्क की कुल संपत्ति 2021 के लास्ट के महीनों में 320 अरब डॉलर थी, जो गिरकर जनवरी 2023 तक 130 अरब डालर हो गई, जिसका मुख्य कारण टेस्ला के स्टॉक का खराब प्रदर्शन है। एलन मस्क की अधिकांश संपत्ति टेस्ला के स्टॉक पर निर्भर करती है, जो 2022 में लगभग 65 फीसदी तक गिर गया है। अक्तूबर में एलन मस्क ने जब से 44 बिलियन डालर में ट्विटर को खरीदा है, तब से टेस्ला के स्टॉक में तेजी से गिरावट हो रही है। हालांकि लगातार गिरावट के बाद भी टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बनी हुई है, जिसका मार्केट कैप अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी टोयोटा से 100 अरब डालर अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार 6.4 फीसदी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर सकेगी

एनटीवी न्यूज

एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार एक फरवरी को बजट पेश करेगी। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है।

सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.4 प्रतिशत के स्तर पर रखने के लक्ष्य को हासिल कर लेगी और अगले वित्त वर्ष में इसमें 0.50 प्रतिशत की कमी आ सकती है। बजट में राजकोषीय मजबूती पर जोर दिये जाने की उम्मीद है। एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार एक फरवरी को बजट पेश करेगी। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है।

राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय का अंतर है। यह घाटा बताता है कि सरकार को व्यय लक्ष्य को पूरा करने के लिये बाजार से कितना उधार लेना होगा। वित्त मंत्री निर्मला

सीतारमण ने हाल में कहा था कि वह बजट के अनुसार राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करेंगी। इसका कारण बजट में तय लक्ष्यों के मुकाबले कर संग्रह अधिक होना है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिंसों के दाम में तेजी के कारण खाद्यान्न और उर्वरक सब्सिडी पर खर्च बढ़ाना पड़ा है।

इससे अधिक कर राजस्व के रूप में सरकार के लिये राजकोष के स्तर पर जो गुंजाइश बनी थी, वह कायम नहीं रह पायी। इसके अलावा सरकार ने मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, ग्रामीण विकास और रक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त खर्च को लेकर मांग भी संसद में रखी। रिपोर्ट में उम्मीद जतायी गयी है कि सरकार बजट में तय लक्ष्य के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 प्रतिशत पर बरकरार रख पाएगी। जिंसों के दाम में तेजी से जो अतिरिक्त सब्सिडी है, उसकी भरपाई बजट से होने की संभावना है।

ब्रोकरेज कंपनी ने यह भी उम्मीद जतायी कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे में 0.5 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। इसका कारण खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी तथा कर राजस्व का अधिक होना है। यानी इसका मतलब है कि देश राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। यह उम्मीद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से बंधी है। दोनों मदों में कर संग्रह बजट अनुमान को पार कर जाने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार विनिवेश लक्ष्य से चूक सकती है।

ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि बजट में मध्यम अवधि में राजकोषीय मजबूती के रास्ते को चुने जाने के साथ पूंजी व्यय, विनिर्माण प्रोत्साहन पर जोर दिये जाने की उम्मीद है जबकि बाजार से कर्ज को इस हद तक सीमित किया जा सकता है, जिससे बाजार पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। यह बजट चुनाव से पहले पेश किया जा रहा है। ऐसे मेंसरकार बुनियादी ढांचे के लिये मुख्य रूप से सड़कों और रेलवे में पूंजी व्यय आवंटन में वृद्धि करेगी। दूसरी तरफ रक्षा खर्च में कमी की जा सकती है और ग्रामीण क्षेत्र और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे कल्याणकारी उपायों को लेकर आवंटन में वृद्धि होगी।

यात्रियों को लिए बगैर ही विमान रवाना होने पर गो फर्स्ट को नोटिस जारी

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बेंगलुरु हवाईअड्डे पर एक यात्री कोच में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही विमान रवाना हो जाने के मामले में सस्ती विमानन कंपनी गो फर्स्ट को मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बेंगलुरु हवाईअड्डे पर एक यात्री कोच में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही विमान रवाना हो जाने के मामले में सस्ती विमानन कंपनी गो फर्स्ट को मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। गो फर्स्ट एयरलाइन की उड़ान संख्या जी8-116 सोमवार को बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली थी लेकिन वह 55 यात्रियों को अपने साथ लिए बगैर ही रवाना हो गई। ये सभी यात्री हवाईअड्डे पर संचालित होने वाली एक बस में सवार थे। डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि कई गलतियों के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई। विमानन नियामक ने कहा, समुचित संचार के अभाव, समन्वय की कमी और पुष्टि नहीं होने से एक टाली जाने लायक स्थिति पैदा हो गई। डीजीसीए ने एयरलाइन के मुख्य परिचालन अधिकारी एवं प्रबंधक को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में कहा है कि निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। एयरलाइन को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। गो फर्स्ट की बेंगलुरु-दिल्ली उड़ान के कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि एक यात्री बस में सवार 50 से अधिक यात्रियों को लिए बगैर ही विमान रवाना हो गया। यह उड़ान सोमवार को शाम छह बजकर 40 मिनट पर रवाना हुई थी।

सेबी ने बिक्री पेशकश नियमों में बदलाव किया

संशोधित नियमों के तहत अब दो बिक्री पेशकश के बीच अंतर को 12 सप्ताह से घटाकर दो सप्ताह कर दिया है। इसके अलावा, खुदरा निवेशकों को दूसरी श्रेणी के बिना अभिदान वाले हिस्से के लिये बोली लगाने की अनुमति दी गयी है।

बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को बिक्री पेशकश (ओएफएस) नियमों में बदलाव किया। इससे उन प्रवर्तकों और बड़े शेयरधारकों के लिये चीजें सरल होंगी, जो बिक्री पेशकश के जरिये अपने शेयर बेचना चाहते हैं। संशोधित नियमों के तहत अब दो बिक्री पेशकश के बीच अंतर को 12 सप्ताह से घटाकर दो सप्ताह कर दिया है। इसके अलावा, खुदरा निवेशकों को दूसरी श्रेणी के बिना अभिदान वाले हिस्से के लिये बोली लगाने की अनुमति दी गयी है। साथ ही सूचीबद्ध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के यूनिट धारकों को अपनी हिस्सेदारी ओएफएस के जरिये पेशकश करने की इजाजत दी गयी है।

संशोधित नियम 10 फरवरी से प्रभाव में आएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र में कहा कि शेयरधारकों का न्यूनतम पेशकश का आकार ओएफएस के जरिये शेयर बिक्री को लेकर 25 करोड़ होना चाहिए। हालांकि, एक ही चरण में न्यूनतम शेयरधारिता हासिल करने के लिये प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह की इकाइयों के लिये पेशकश का आकार 25 करोड़ रुपये से कम हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि सेबी निदेशक मंडल ने सितंबर में ओएफएस के जरिये शेयरों की पेशकश को लेकर गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों के मामले में न्यूनतम 10 प्रतिशत शेयरधारिता की आवश्यकता को खत्म करने का फैसला किया था। बिक्री पेशकश व्यवस्था उन कंपनियों के लिये उपलब्ध है, जिनका बाजार पूंजीकरण 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। सेबी ने दो ओएफएस के बीच अंतराल के बारे में कहा कि मौजूदा 12 सप्ताह से अधिक के अंतर को कम कर दो सप्ताह से 12 सप्ताह से अधिक कर दिया गया है। यह पात्र कंपनियों के प्रतिभूतियों की बिक्री को लेकर स्थिति पर निर्भर करेगा। हालांकि, कंपनियों के प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह की इकाइयां, जिनके शेयरों का कारोबार अधिक या कम होता है, वे अपने शेयर ओएफएस या पात्र संस्थागत नियोजन के जरिये दो सप्ताह के अंतर पर पेश कर सकते हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार करार से परिधान निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगा

भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत सीमा शुल्क का लाभ मिलने से भारतीय परिधान निर्यातकों को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उस देश में अधिक बाजार पहुंच कायम करने में मदद मिलेगी। परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) ने मंगलवार को यह बात कही।

नयी दिल्ली। भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत सीमा शुल्क का लाभ मिलने से भारतीय परिधान निर्यातकों को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उस देश में अधिक बाजार पहुंच कायम करने में मदद मिलेगी। परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) ने मंगलवार को यह बात कही। यह समझौता 29 दिसंबर से लागू हो रहा है। एईपीसी के उपाध्यक्ष सुधीर सेखरी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक है।

जहां ऑस्ट्रेलिया में परिधान के आयात में चीन की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक की है, वहीं भारत की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा, ''भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए (आर्थिक सहयोग और व्यापार करार) के लागू होने के साथ भारत को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में आयात के लिए वियतनाम और इंडोनेशिया के मुकाबले मामूली शुल्क लाभ होगा।''

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के तैयार परिधान निर्यात में पिछले पांच वर्षों में औसतन 11.84 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो ''विशुद्ध रूप से अधिकांश देशों द्वारा अपनाई गई 'चीन प्लस वन रणनीति' के कारण है।'' उपाध्यक्ष ने कहा कि विकास की इस प्रवृत्ति को देखते हुए और समझौते के लागू होने से एईपीसी का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को निर्यात वर्ष 2025 तक तीन गुना बढ़ जाएगा।

वाणिज्य विभाग द्वारा मंगलवार को एईपीसी और ओखला गारमेंट टेक्सटाइल्स क्लस्टर (ओजीटीसी) के सहयोग से परिधान निर्यातकों के साथ एक पहुंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओजीटीसी के अध्यक्ष पी एम एस उप्पल ने कहा कि अधिकांश बड़ी ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों की चीन में गहरी जड़ें हैं और वे भारत को केवल एक विकल्प के रूप में मानेंगी। यदि हम उन्हें आकर्षक प्रोत्साहन देते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तभी वे भारत का रुख करेंगी।'' सरकार ने एईपीसी को आश्वासन दिया है कि वह चुनौतियों पर गौर करेगी और सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी।

माइकल पात्रा फिर बने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर

नई दिल्ली। केंद्र ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा को 15 जनवरी से एक साल के लिए फिर से नियुक्त किया है। यह फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लिया। पात्रा 1985 से करियर केंद्रीय बैंकर हैं। उन्होंने 14 जनवरी, 2020 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने केंद्रीय बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में, वह आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य थे, जिसे भारत में मौद्रिक नीति निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह डिप्टी गवर्नर के रूप में एमपीसी के पदेन सदस्य बने रहेंगे। इससे पहले, वह जुलाई 2012 और अक्टूबर 2014 के बीच आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग के प्रधान सलाहकार थे।

मोहन भागवत के साक्षात्कार ने सर्द मौसम में बढ़ाया राजनीतिक तापमान

अपने साक्षात्कार में मोहन भागवत ने कहा, ''इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनें...यह छोड़ना पड़ेगा।'' साथ ही, भागवत ने कहा ''ऐसा सोचने वाला कोई हिन्दू है, उसे भी (यह भाव) छोड़ना पड़ेगा।

एनटीवी न्यूज

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के एक साक्षात्कार ने सर्द मौसम में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। पिछले कुछ समय से मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनने और उन्हें अपने साथ जोड़ने की मुहिम चला रहे आरएसएस प्रमुख ने कहा है मुसलमानों को 'हम बड़े हैं' का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने कहा है कि हिन्दू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे 'हम बड़े हैं' का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत के इस बयान पर विवाद भी खड़ा हो गया है। शिवसेना ने कहा है कि लोगों के मन में डर पैदा करके राजनीति करना गलत है। वहीं जहां तक भागवत के बयान की बात है तो हम आपको बता दें कि उन्होंने 'ऑर्गेनाइजर' और 'पांचजन्य' को दिये साक्षात्कार में कहा है कि हिन्दू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृति है। आरएसएस सरसंघचालक ने कहा, ''हिन्दुस्थान, हिन्दुस्थान बना रहे, सीधी-सी बात है। इससे आज भारत में जो मुसलमान हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। वह हैं। रहना चाहते हैं, रहें। पूर्वज के पास वापस आना चाहते हैं, आएं। उनके मन पर है।''

अपने साक्षात्कार में मोहन भागवत ने कहा, ''इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनें...यह छोड़ना पड़ेगा।'' साथ ही, भागवत ने कहा ''ऐसा सोचने वाला कोई हिन्दू है, उसे भी (यह भाव) छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा।'' भागवत के इस बयान पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि देश में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। अगर चुनाव जीतने के लिए राजनीति करने के लिए आप बार-बार हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश फिर टूट जाएगा और फिर विभाजन की स्थिति पैदा होगी। सांसद संजय राउत ने कहा कि लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर मोहन भागवत जी ने ये बात सामने रखी है तो भाजपा को इस पर गौर करना चाहिए।

उधर, 'ऑर्गेनाइजर' और 'पांचजन्य' को दिये साक्षात्कार में सरसंघचालक मोहन भागवत ने आश्चर्यजनक रूप से एलजीबीटी समुदाय का समर्थन किया और कहा कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा, ''इस तरह के झुकाव वाले लोग हमेशा से थे, जब से मानव का अस्तित्व है...यह जैविक है, जीवन का एक तरीका है। हम चाहते हैं कि उन्हें उनकी निजता का हक मिले और वह इसे महसूस करें कि वह भी इस समाज का हिस्सा है। यह एक साधारण मामला है।'' उन्होंने कहा, ''तृतीय पंथी लोग (ट्रांसजेंडर) समस्या नहीं हैं। उनका अपना पंथ है, उनके अपने देवी देवता है। अब तो उनके महामंडलेश्वर हैं।'' उन्होंने कहा कि संघ का कोई अलग दृष्टिकोण नहीं है, हिन्दू परंपरा ने इन बातों पर विचार किया है।

जनसंख्या नीति के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में भागवत ने कहा कि पहले हिन्दू को यह समझ में आए कि हिन्दू आज बहुमत में है तथा हिन्दू के उत्थान से इस देश के सब लोग सुखी होंगे। उन्होंने कहा, ''जनसंख्या एक बोझ भी है और एक उपयोगी चीज भी है, ऐसे में जैसा मैंने पहले कहा था कि वैसी दूरगामी और गहरी सोच से एक नीति बननी चाहिए।'' सरसंघचालक ने कहा, ''यह नीति सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए लेकिन इसके लिये जबर्दस्ती से काम नहीं चलेगा। इसके लिए शिक्षित करना पड़ेगा।'' उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन अव्यवहार्य बात है क्योंकि जहां असंतुलन हुआ, वहां देश टूटा, ऐसा सारी दुनिया में हुआ।

भागवत ने कहा कि एकमात्र हिन्दू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है, इसलिये अनाक्रामकता, अहिंसा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता...यह सब बचाये रखना है। उन्होंने कहा, ''तिमोर, सूडान को हमने देखा, पाकिस्तान बना, यह हमने देखा। ऐसा क्यों हुआ? राजनीति छोड़कर अगर तटस्थ होकर विचार करें कि पाकिस्तान क्यों बना?'' उन्होंने कहा, ''जब से इतिहास में आंखें खुली तब भारत अखंड था। इस्लाम के आक्रमण और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद यह देश कैसे टूट गया.. यह सब हमको इसलिये भुगतना पड़ा क्योंकि हम हिन्दू भाव को भूल गए।''

भागवत ने कहा, ''हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। इस देश में हिन्दू रहेगा, हिन्दू जायेगा नहीं, यह अब निश्चित हो गया है। हिन्दू अब जागृत हो गया है। इसका उपयोग करके हमें अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना और हमारे पास जो समाधान है, उसे प्रस्तुत करना है।'' भागवत ने कहा, ''नयी नयी तकनीक आती जायेगी। लेकिन तकनीक मनुष्यों के लिये है। कृत्रिम बुद्धिमता को लेकर लोगों को डर लगने लगा है। वह अगर निर्बाध रहा तो कल मशीन का राज हो जायेगा।''

सांस्कृतिक संगठन होने के बावजूद राजनीतिक मुद्दों के साथ आरएसएस के जुड़ाव पर, भागवत ने कहा कि संघ ने जानबूझकर खुद को दिन-प्रतिदिन की राजनीति से दूर रखा है, लेकिन हमेशा ऐसी राजनीति से जुड़ा है जो ''हमारी राष्ट्रीय नीतियों, राष्ट्रीय हित और हिन्दू हित'' को प्रभावित करती है।

उधर, राहुल गांधी की ओर से आरएसएस पर किये जा रहे हमलों की बात करें तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें कुछ दिन आरएसएस की शाखा में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि वह संगठन के बारे में कुछ नहीं जानते। राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरवों का संगठन बताया था। इस बारे में पूछे जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी से कांग्रेस के नेता भी हैरान हैं। खट्टर ने कहा, "वह पप्पू ही हैं।" राहुल गांधी की टिप्पणी पर खट्टर ने पत्रकारों से कहा, "वह जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, समझ नहीं आता कि वह किस दर्शन का पालन करते हैं...।" उन्होंने कहा, "कभी वह शिव भक्त बन जाते हैं और फिर पूछते हैं कि (हर हर महादेव) जयकारा कौन लगाता है। कभी वह पुजारियों को निशाना बनाने लगते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि उनकी दिशा क्या है... ऐसा नहीं है कि केवल हम ही हैरान हैं। कांग्रेस के लोग भी हैरान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "वैसे भी, वह पप्पू ही हैं।"

इनसाइड

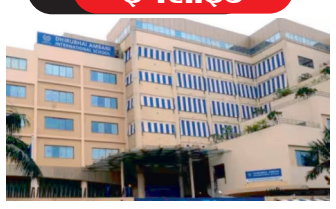

धीरूभाई अंबानी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, कॉलर ने कहा- हमने रखा है बम

मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने का कॉल आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने कॉलर को ट्रेस कर लिया है। मगर अब तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटनरेशनल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी यानी मंगलवार को स्कूल में धमकी भरा कॉल आया था, जिसमें एक अनजान व्यक्ति ने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक कॉलर ने 4.30 बजे फोन पर कहा कि स्कूल में टाइम बम लगा है। इसके बाद फोन काट दिया गया। इस फोन कॉल से हर तरफ हड़कंप और अफरातफरी का माहौल हो गया। स्कूल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 505 (1) (B) और धारा 506 के तहत अज्ञात कॉलर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि जहां से ये कॉल आया था उसे ट्रेस कर लिया गया है। जल्द ही पुलिस कॉल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करेगी। बता दें कि इससे पहले रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल को भी बम से उड़ाने का कॉल बीते वर्ष अक्टूबर में किया गया था।

पंजाब में सरकार-अफसरशाही के बीच तकरार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ताली अधिकारी को रात दो बजे तक का समय दिया है। उन्होंने दो बजे तक ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि देखने में आया है कि कुछ अधिकारी अपनी ड्यूटी छोड़कर हड़ताल पर हैं। पिछले लंबे समय से पंजाब सरकार और प्रशासन के बीच खींचतान चल रही हैं।लुधियाना के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) की विजिलेंस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद से ही पंजाब के PCS अधिकारी स्ट्राइक पर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ताली अधिकारी को दो बजे तक का समय दिया है।

पश्चिम बंगाल पर भाजपा की नजर, TMC को घेरने के लिए बना रही यह रणनीति

एनटीवी संवाददाता

पार्टी की ओर से संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। पार्टी मंडल और बूथ स्तर की कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। भाजपा अपने जनसंपर्क अभियान को मार्च-अप्रैल में शुरू करेगी। फिलहाल इसको लेकर तैयारी और योजना पर काम किया जा रहा है।

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अभी से ही रणनीति बनाने की शुरुआत कर दी है। भाजपा की नजर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों पर है। इन राज्यों में भाजपा अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सफलता हासिल करने वाली भाजपा ने 2024 के लिए भी पूरी ताकत लगा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में जनसंपर्क अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इस प्रक्रिया के तहत पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता जनता से मिलेंगे और मोदी सरकार द्वारा किए गए काम का जो पर प्रतिक्रिया मांगेंगे। इसी दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का भी वह प्रचार करेंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी मुद्दा जनता के सामने रखेंगे।

इतना ही नहीं, पार्टी की ओर से संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। पार्टी मंडल और बूथ स्तर की कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। भाजपा अपने जनसंपर्क अभियान को मार्च-अप्रैल में शुरू करेगी। फिलहाल इसको लेकर तैयारी और योजना पर काम किया जा रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि बीजेपी बंगाल फिलहाल संभागीय जिला बूथ स्तर पर सभी कमेटियों के पुनर्गठन पर काम कर रही है। बूथ और मंडल स्तर पर समितियों के चेहरों में भी बदलाव हो रहा। 21 जनवरी को बंगाल राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें पार्टी आगे की योजनाओं पर चर्चा करेगी और उन को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। फिलहाल संगठन में गैप को भरने की कवायद जारी है।

पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखते हुए कई केंद्रीय मंत्रियों को भी काम पर लगा दिया गया है। इनमें धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, पंकज चौधरी और साध्वी निरंजन ज्योति शामिल है। इन सभी को कुछ लोकसभा सीटें आवंटित की गई है जहां यह जाते रहेंगे और बैठक भी करते रहेंगे। जमीनी स्तर पर पार्टी के हिसाब से यह जानकारी एकत्रित करेंगे बताया जा रहा है कि दौरे का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं।

कूनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे और चीते, फरवरी से सफारी कर सकेंगे पर्यटक: चौहान

चौहान ने यहां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह में कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को 'टाइगर रिजर्व' सहित मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का दौरा करना चाहिए।

इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि राज्य के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जल्द ही और चीते लाए जाएंगे। देश में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत पिछले साल सितंबर में नामीबिया से लाए गए आठ चीते पार्क में छोड़े गए थे। चौहान ने यहां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह में कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को 'टाइगर रिजर्व' सहित मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''आप फरवरी से चीतों को देखने के लिए आएं। हम फरवरी से (पर्यटकों की यात्रा) की अनुमति देंगे।'' चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से चीतों को लाने का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही उन्होंने कहा, ''दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाए जा रहे हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को विदेश में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों के छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित करनी चाहिए।

धंस रहा है जोशीमठ! आशियाने पर बुलडोजर चलता देखकर घबराए लोग, कर रहे हैं सरकार से मुआवजे की मांग

एनटीवी संवाददाता

राज्य सरकार ने 'माउंट व्यू' और 'मालारी इन' होटलों को गिराने का फैसला किया जिनमें हाल में बड़ी दरार आ गयीं और दोनों एक-दूसरे की ओर झुक गये हैं। इससे आसपास की इमारतों को खतरा पैदा हो गया है।

उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित जोशीमठ में मंगलवार को दो जर्जर हो चुके होटलों को गिराए जाने से पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने विध्वंस गतिविधियों के खिलाफ नारे लगाए क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि जिन लोगों की संपत्तियों को गिराया जाना था उन्हें मुआवजा कैसे दिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत मुआवजे की मांग को लेकर होटल मालिक और स्थानीय लोग होटलों को गिराने के सरकार के कदम का विरोध कर रहे थे। जोशीमठ प्रशासन ने उन सभी अधिकारियों और होटल मालिकों की बैठक बुलाई है जिनकी संपत्तियों को तोड़ा जाना है। स्थानीय लोग और होटल मालिक मलारी होटल के पास धरने पर बैठ गए और मुआवजे के आश्वासन के बिना जाने को तैयार नहीं थे।

मानव बस्तियों को खतरा

राज्य सरकार ने 'माउंट व्यू' और 'मालारी इन' होटलों को गिराने का फैसला किया जिनमें हाल में बड़ी दरार आ गयीं और दोनों एक-दूसरे की ओर झुक गये हैं। इससे आसपास की इमारतों को खतरा पैदा हो गया है। इलाके में अवरोधक लगा दिये गये हैं और इन होटल तथा आसपास के मकानों में बिजली आपूर्ति रोक दी गयी है जिससे करीब 500 घर बिजली के अभाव का सामना कर रहे हैं। राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) के कर्मी जेसीबी के साथ मौके पर पहुंच गये हैं और लोगों को इन होटल से दूरी बनाने को कहा गया है। हालांकि, जब प्रशासन शाम को 'मलारी इन' को गिराने वाला था तो इसके मालिक ठाकुर सिंह विरोध स्वरूप होटल के सामने सड़क पर लेट गये। होटल मालिकों ने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से इस बारे में पता चला। उन्होंने मांग की कि होटल गिराने से पहले उन्हें एकमुश्त निपटान के लिए प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलना चाहिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कस्बे के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए जनहित में विध्वंस की कार्रवाई की जा रही है। आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की को होटलों को गिराने के काम में लगाया गया है। लोगों को घरों से निकालने के प्रयास जारी रहने के बीच अब तक कुल 131 परिवार अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंच गये हैं, वहीं जोशीमठ में दरार पड़ने और जमीन धंसने से प्रभावित घरों की संख्या 723 हो गयी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चमोली इकाई ने मंगलवार को एक बुलेटिन में यह जानकारी दी। क्षेत्र में 86 घरों को असुरक्षित चिह्नित किया गया है।

विध्वंस के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध

स्थानीय निवासियों ने जोशीमठ के पहाड़ी शहर में, बिना मुआवजे की घोषणा के, उत्तराखंड प्रशासन द्वारा डूबते घरों और होटलों को गिराने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन मलारी इन होटल के बाहर हुआ, जिसे असुरक्षित चिन्हित किया गया था। होटल मलारी इन और अन्य असुरक्षित ढांचों को बुधवार को गिराया जाना है। प्रदर्शनकारी अचानक विध्वंस के कदम के लिए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि शाम होते-होते प्रशासन मलारी इन को गिराने ही वाला था कि इसके मालिक ठाकुर सिंह विरोध स्वरूप होटल के सामने सड़क पर लेट गए। गिराने की प्रक्रिया बुधवार रात से शुरू होने की संभावना है।

800 घर क्षतिग्रस्त

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चमोली द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड के जोशीमठ में क्षतिग्रस्त घरों की संख्या 800 हो गई है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूस्खलन के कारण कुल 800 भवनों में दरारें आ गई हैं और 131 परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्तराखंड के डूबते शहर जोशीमठ के स्थानीय लोग संकट के कारण गुस्से और निराशा के बीच एक अंधकारमय भविष्य की ओर देख रहे हैं। जोशीमठ में 344 राहत शिविर और 491 कमरों की पहचान की गई है। क्षेत्र में 86 घर असुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित हैं।जिला प्रशासन ने डूबते शहर में रहने के लिए असुरक्षित घरों पर रेड क्रॉस के निशान लगा दिए हैं। इस बीच, घरेलू सामान खरीदने के लिए परिवारों को 5,000 रुपये और 10 क्षतिग्रस्त भवनों के मालिकों को 1.30 लाख रुपये प्रति भवन दिए गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को भोजन किट, दूध और कंबल भी वितरित किए।